@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नई दिल्ली, शनिवार, 28 नवंबर 2026, वर्ष-2, अंक-38, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

अर्शी खान ने ऐसे बदली अपनी किस्मत ...पेज-8



लोकसभा में बढ़ेंगी 50 प्रतिशत सीटें, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव, 2029 के चुनाव से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी।



केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, नए परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन को वर्ष 2051 तक यथावत रखने का प्रस्ताव है।

सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से सोमवार से आरंभ हो रही संसद की विशेष बैठक में तीन विधेयक पेश करेगी। इनमें दो संविधान संशोधन विधेयक होंगे, जबकि तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित होगा।

सरकार का मानना है कि प्रस्तावित विधेयकों में किए गए बदलावों से उन विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल सकता है, जिन्होंने इस साल अप्रैल में लाए गए पिछले विधेयक का विरोध किया था।

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सरकार को तीनों विधेयकों के संसद से पारित होने का पूरा भरोसा है।

सरकार से जुड़े एक सूत्र ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार तीनों विधेयक पारित हो जाएंगे। हमने कई राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से विचार-विमर्श किया है और उनका पूरा आश्वासन मिलने के बाद ही विशेष बैठक बुलाने का फैसला किया है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 होगी, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे। इसके अलावा, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर प्रत्येक राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या भी इसी अनुपात में बढ़ाने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जबकि राज्यों के बीच निर्वाचन क्षेत्रों के अनुपात का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों की उन आशंकाओं को दूर करना है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण परिसीमन के बाद संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा में राज्य की मौजूदा 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि द्रमुक की इस मांग का ध्यान रखा जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, नए परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तथा सीटों का आवंटन 25 साल तक यानी 2051 तक स्थिर रखा जाएगा और इस अवधि में इनमें कोई बदलाव नहीं होगा।

महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण शुरुआत में 15 साल के लिए होगा। इसके बाद संसद कानून बनाकर इसकी अवधि बढ़ा सकेगी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन प्रत्येक कार्यकाल के बाद किया जाएगा। आरक्षण की अवधि बढ़ाने का फैसला उस समय की सरकार करेगी।

सरकार संविधान के दो संशोधन विधेयक लाएगी। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत परिसीमन आयोग के गठन और संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से संबंधित प्रावधान होंगे। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में आवश्यक बदलाव के लिए अलग विधेयक पेश किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नया संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 अप्रैल में लोकसभा में पारित नहीं हो पाने वाले विधेयक से काफी अलग होगा। इसमें संविधान के कम से कम आठ अनुच्छेदों में व्यापक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव कर रही है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद राज्य के विभाजन की किसी भी आशंका को दूर करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 403 सीटें हैं। प्रस्तावित वृद्धि के बाद इनकी संख्या 600 से अधिक हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं चाहती और इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया जाएगा। हालांकि, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का फार्मूला लागू नहीं होगा। वहीं, नगालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में जहां लोकसभा की एक-एक सीट है, वहां सीटों की संख्या बढ़ाकर दो किए जाने की संभावना है। इस संबंध में अंतिम निर्णय राजनीतिक और व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसी कारण विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

अब परिसीमन के जरिये संविधान बदलने की कोशिश में सरकार : कांग्रेस



नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में '400 पार' नारे के साथ विफल रहने के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार अब परिसीमन के जरिये संविधान बदलने की कोशिश में जुटी है, लेकिन वह अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास पर हुई पार्टी की संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में अगले सप्ताह प्रस्तावित संसद की बैठक तथा परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई।

इस बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार का लक्ष्य परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर वह काम करने का है, जिसे वह पिछले लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे के बावजूद नहीं कर पाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन आयोग के गठन और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

गोगोई ने कहा कि कांग्रेस की मांग स्पष्ट है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या और हर राज्य की लोकसभा सीटों की सीटों की संख्या को भी बरकरार रखा जाए तथा इसमें 25 साल तक कोई बदलाव नहीं होने चाहिए।

उनके मुताबिक, कांग्रेस की मांग यह भी है कि 543 सीटों में ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। गोगोई ने आरोप लगाया, सरकार पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाता सूची में कथित हेरफेर के जरिये यह तय करने की कोशिश कर रही है कि कौन मतदान कर सकता है और कौन नहीं। अब परिसीमन के जरिये यह तय करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कहां मतदान कर सकेगा।''

उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिस आयोग के कामकाज को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं, उससे जुड़ी व्यवस्था में परिसीमन की प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा संसद को सुचारू रूप से चलाने की नहीं है।

उन्होंने कहा कि एक दिन में 140 से अधिक सांसदों को निलंबित करने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देने वाला विधेयक पारित किया गया था।

गोगोई ने कहा, ''इनका सपना था कि 400 पार करके संविधान के ढांचे और उसके मूल स्वरूप को बदलेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए।

सार समाचार

भागवत ने मानव के लिए करुणा को बताया आवश्यक

नई दिल्ली,एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मानव के लिए करुणा को आवश्यक बताते हुए कहा है कि मानव जाति अकेले सुखी नहीं रह सकती है तथा पूरा संसार सुखी होगा, पर्यावरण स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा, तभी मानव सुखी होगा। श्री भागवत शुक्रवार को यहां नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किताब 'करुणानायक राम' के विमोचन के मौके पर राम और रावण के बीच का फर्क समझाया। उन्होंने कहा, जब हम महान व्यक्तियों का जीवन पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान आमतौर पर इस बात पर रहता है कि उन्होंने क्या किया। हम उनके काम देखते हैं और उन्हें आदर्श मानते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि एक शब्द सामने आया कि रावण अहंकारी था, जबकि राम करुणा के प्रतीक थे। रावण को अपने बल, अपने ज्ञान और अपने साम्राज्य पर अहंकार था। वह मैं और मेरा से आगे नहीं जा पाया। राम इसके ठीक उल्टे थे।उन्होंने कैलाश सत्यार्थी की इस पुस्तक को सुखी जीवन जीने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बताया। समारोह में भूटान की राजकुमारी सोनम देचन वांगचुक और राजपरिवार के कई अन्य सदस्य तथा केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मौजूद थे।

गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में किया बदलाव

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन किया है, जिसके तहत, पंजीकरण और देशीयकरण (नेचुरलाइजेशन) के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों को डिजिटल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जबकि भौतिक प्रमाण पत्र केवल अनुरोध करने पर ही जारी किये जाएंगे। शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में, मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल नागरिकता प्रमाण पत्र केंद्र के अवर सचिव या इसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि आवेदक अनुरोध करता है, तो भौतिक प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण का डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा... जिस पर भारत सरकार के अवर सचिव या इससे उच्च पद के अधिकारी, या केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर या सामान्य हस्ताक्षर होंगे। देशीयकरण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति उस देश की नागरिकता प्राप्त करता है, जहां उसका जन्म नहीं हुआ हो।

टाटा संस की बोर्ड बैठक पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

मुंबई, एजेंसी।



बंबई उच्च न्यायालय ने टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली टाटा ट्रस्ट की याचिकाओं पर शुक्रवार को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने 30 नवंबर को होने वाली कंपनी की बोर्ड बैठक को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन स्पष्ट किया कि उसमें लिए गए फैसले उसके अंतिम आदेश के अधीन होंगे।

न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ ने टाटा संस और अन्य प्रतिवादियों को याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी, 2027 को होगी।

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और आरडी टाटा ट्रस्ट ने चंद्रशेखरन को तीसरी बार कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी है। ट्रस्ट ने बोर्ड बैठक टालने और चेयरमैन को मतभेद की स्थिति में निर्णायक मत का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी।

याचिकाओं में दावा किया गया कि 17 सितंबर को चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 121 के तहत जरूरी समर्थन मत हासिल नहीं कर सका था, इसलिए यह अमान्य है।

यह विवाद टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के मुद्दे पर टाटा ट्रस्ट और कंपनी प्रबंधन के बीच मतभेद के बीच सामने आया है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पूरा होने के करीब: गोयल

नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पूरा होने के करीब है और समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तथा रूपरेखा अब आकार ले रही है। गोयल ने 'इंडिया डेट कैपिटल मार्केट समिट 2026' को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पूरा होने के करीब है। वह प्रक्रिया और मार्ग, जिसकी वजह से समझौते को अंतिम रूप देने में हमेशा रुकावट आती थी, उसमें अब कुछ बात बन रही है।

उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की ताजा रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

समुद्री जहाजों और नाविकों पर हमले बर्दाश्त नहीं: जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी।



विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा समुद्री जहाजों एवं नाविकों पर बढ़ते हमलों को बिल्कुल अस्वीकार्य करार देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के सभी तटीय देशों को इसकी सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

'हिंद महासागर रिम एसोसिएशन' (आईओआरए) की एक मंत्री-स्तरीय बैठक में अपने संबोधन के दौरान, जयशंकर ने समुद्री कानूनों, विशेष रूप से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते (यूएनसीएलओएस) का सम्मान करने की अपील की। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक समुद्री क्षेत्र में विवाद बढ़ रहे हैं, जिसमें दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना भी शामिल है। भारत ने आईओआरए के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नयी दिल्ली में इस सम्मेलन की मेजबानी की। इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, सोमालिया, ओमान, यमन, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड सहित 23 देश शामिल हैं।

अमेरिका, यूरोपीय संघ और आईओआरए के कई अन्य संवाद साझेदार भी इस बैठक में शामिल हुए। अपनी टिप्पणी में, जयशंकर ने उस विषय पर चर्चा की जिसे उन्होंने बदलती वैश्विक व्यवस्था के अस्थिर पहलू कहा तथा संघर्षों, टकरावों और व्यवधानों के प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, हिंद महासागर अपने समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से तैयार है। वैश्विक विकास के लिए समुद्री व्यापार के महत्व को समझते हुए, हमें इसकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्री ने कहा कि समुद्री जहाजों और नाविकों पर हमले बिल्कुल अस्वीकार्य हैं और इनके खिलाफ वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया की जरूरत है। जयशंकर की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब पश्चिम एशिया और काला सागर में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं। इन हमलों में कई भारतीय नाविकों की मौत हुई है। उन्होंने कहा, चाहे आतंकवाद का मुकाबला करना हो, नशीले पदार्थों का व्यापार हो, या फिर अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और मछली पकड़ने की अनियंत्रित गतिविधियां हों; इसके अलावा जलवायु संबंधी घटनाओं और आपदा की स्थितियों से निपटना हो - हमें और अधिक आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है।

शीर्ष अदालत ने अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के न्यासी मंडल को निलंबित कर दिया

कार्तिगई दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दीपक जलाने का दिया आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी।



तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने संबंधी अपने आदेश का जानबूझकर और खुलेआम उल्लंघन किए जाने से नाराज उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किये और कहा कि कार्यपालिका के अधिकारियों ने अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देशों पर काम किया।

शीर्ष अदालत ने अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के न्यासी मंडल को निलंबित कर दिया और उच्चिपिल्लैयार मंडपम में 24 नवंबर को प्रज्वलित दीप की लौ से शनिवार को तिरुप्परनकुंद्रम के दीपथून पर दीप प्रज्वलित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए अधिकारियों के बीच हुए ई-मेल, फोन पर हुई बातचीत और संदेशों के आदान-प्रदान का विस्तृत विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, अदालत के आदेशों का जानबूझकर अनुपालन नहीं किए जाने, विशेषकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसा किए जाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इससे सख्ती से निपटना होगा।

पीठ ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के सचिव और आयुक्त, मदुरै के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, मंदिर के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित लोगों को अवमानना नोटिस जारी किये। शीर्ष अदालत ने अपने आदेशों को लागू करने में तमिलनाडु पुलिस की विफलता का हवाला देते हुए अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर और तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को सौंप दिया। यह कार्रवाई 20 नवंबर को कार्तिगई दीपम के संबंध में दिए गए शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर की गई।

न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों का आचरण प्रथम दृष्टया तमिलनाडु में, या कम से कम मदुरै जिले में, प्रशासनिक अराजकता की स्थिति को उजागर करता है।

पीठ ने कहा, ''रिकॉर्ड में सामने आए आरोपों के अनुसार, अधिकारियों का कथित आचरण प्रथम दृष्टया इस अदालत के आदेश की खुलेआम और जानबूझकर अवहेलना, उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन की घोर अनदेखी और दोनों संवैधानिक अदालतों के अधिकार को चुनौती देने की सोची-समझी कोशिश को दर्शाता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु के कार्यपालिका के अधिकारी यह तय नहीं कर सकते कि न्यायिक आदेशों का पालन किया जाना चाहिए या नहीं।

पीठ ने जोर देकर कहा कि कानून का शासन सर्वोपरि है और भारत के हर कोने में सभी नागरिक एवं न्यायिक प्राधिकरणों का कर्तव्य है कि वे शीर्ष अदालत के कामकाज में सहयोग करें और उसके आदेशों को प्रभावी बनाने में सहायता दें।

शीर्ष अदालत ने कहा, इस अदालत का कोई आदेश बातचीत या मोलभाव का निमंत्रण नहीं होता। जब तक यह अदालत स्वयं उसमें संशोधन नहीं करती, तब तक उसका आदेश राज्य सरकार, उसके अधिकारियों और राज्य के कानून के तहत काम करने वाली प्रत्येक वैधानिक या धार्मिक संस्था पर बाध्यकारी होता है।

युद्ध व शांति के बीच का अंतर धुंधला पड़ रहा : सीडीएस

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने शुक्रवार को कहा कि आज युद्ध और शांति के बीच का अंतर धुंधला पड़ रहा है और लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के ढांचे को आधुनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य की युद्धकला और बहु-क्षेत्रीय अभियान संचालित करने की भारत की तैयारी' विषय पर संबोधन देते हुए जनरल सुब्रमणि ने विस्तार से बताए बिना कहा कि विरोधी पक्ष हम पर गुप्त तरीके से सोच और धारणा को प्रभावित करने वाला युद्ध थोप रहा है।

उन्होंने सभी क्षेत्रों में क्षमताएं बढ़ाने पर जोर दिया।

सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर को संयुक्त, एकीकृत तथा बहु-क्षेत्रीय अभियानों का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि तनाव बढ़ने पर भारत किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार था और इसके परिणामस्वरूप भारत को निर्णायक जीत मिली। पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) रहे सेवानिवृत्त जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में विचारक संस्था 'विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन' की ओर से आयोजित इस सत्र का संचालन किया। जनरल राजा सुब्रमणि ने अपने संबोधन में प्रौद्योगिकी और युद्ध के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता केवल अस्थायी होती है और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहने के वास्ते इसमें लगातार सुधार करना होगा।

नर्सरी एडमिशनः स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की तैयारी तेज

प्रक्रिया में पारदर्शिता और सभी आवेदकों को समान अवसर देने पर जोर रहेगा।

गुरुग्राम,एजेंसी।



नन्हे बच्चों के स्कूल में दाखिले को लेकर अभिभावकों की दौड़ शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी प्रवेश की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में नर्सरी प्रवेश के लिए केंद्रीकृत कार्यक्रम और तारीखों की घोषणा के बीच गुरुग्राम में निजी स्कूल अपने-अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है तो कहीं सीटों की संख्या और प्रवेश के मानदंड तय कर आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

बड़े स्कूलों ने प्रवेश कार्यक्रम और सीटें निर्धारित कर ली हैं, जबकि बजट स्कूल जनवरी से दाखिले शुरू करने की तैयारी में हैं। इस बार नर्सरी प्रवेश में बच्चे की आयु सबसे अहम मानदंड रहने वाली है। 31 मार्च 2027 तक तीन वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे ही संबंधित आयु मानदंड के तहत पात्र होंगे। ऐसे में अभिभावक स्कूलों के चक्कर लगाने के साथ प्रवेश नियमों और सीटों की जानकारी जुटाने में लगे हैं। नए सत्र में नर्सरी प्रवेश के लिए उम्र का मानदंड अहम रहेगा। स्कूलों की ओर से जारी प्रवेश सूचनाओं के अनुसार 31 मार्च 2027 तक तीन वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को नर्सरी में प्रवेश के लिए पात्र माना जा रहा है। कई स्कूलों ने उम्र के मामले में किसी तरह की छूट नहीं देने का स्पष्ट उल्लेख किया है।

ऐसे में अभिभावकों को आवेदन से पहले बच्चे की जन्मतिथि और संबंधित स्कूल के आयु मानदंड की जांच करने की सलाह दी जा रही है। हरियाणा में प्रवेश संबंधी नियमों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शुरुआती कक्षाओं में उम्र का निर्धारण किया जा रहा है। हालांकि स्कूलों में कक्षा के नाम और प्रवेश स्तर में अंतर होने के कारण कहीं तीन वर्ष की आयु पर प्री-नर्सरी तो कहीं नर्सरी में प्रवेश दिया जाता है। अजंता पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल वैभव कपूर के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूल में नर्सरी की कुल 50 सीटें निर्धारित की गई हैं और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 रखी गई है। तीन वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे प्रवेश के लिए पात्र होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। स्कूल का प्रयास है कि मार्च 2027 तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। निर्धारित तारीख के बाद 31 मार्च तक केवल सीटें उपलब्ध होने की स्थिति में प्रवेश दिए जाएंगे।

प्रक्रिया में पारदर्शिता और सभी आवेदकों को समान अवसर देने पर जोर रहेगा।सीडी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर यशपाल यादव के अनुसार, स्कूल में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार दाखिले किए जाएंगे। अभिभावकों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रवेश संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। सीटों और पात्रता के मानदंड के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

अस्पताल में मासूम की मौत के बाद हंगामा

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।



नॉलेज पार्क के एक निजी अस्पताल में गुरुवार की रात मासूम की मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। किसान संगठन के लोगों ने इलाज में लापरवाही और अधिक बिल वसूलने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। नॉलेज पार्क थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जेवर के झुप्पा गांव के रहने वाले हंसराज ने करीब एक महीने पहले अपने ढाई महीने के पोते को नॉलेज पार्क स्थित एक अस्पताल में भर्ती करवाया था।

अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार की रात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पिछले एक महीने में इलाज के दौरान करीब 15 लाख रुपये अस्पताल प्रबंधन ने वसूल लिए। इसके बाद भी बच्चे की जान नहीं बचा सके। अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे की मौत के बाद भी शव देने से पहले तीन लाख रुपये की मांग की। इससे परिजन भड़क गए।परिजनों की सूचना पर किसान संगठन के लोग अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और अधिक बिल वसूलने का आरोप लगाकर नारेबाजी की। अस्पताल परिसर में कई घंटे तक हंगामा चला।

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया। किसी तरह दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद अस्पताल से परिजन बच्चे का शव लेकर गांव रवाना हुए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बिल को लेकर अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच विवाद हुआ था, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से आपस में निपटा लिया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के 50 लाख रुपये के बंपर ड्रॉ में पांच विजेताओं की चमकी किस्मत

अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा ने निकाला ग्रैंड फिनाले का लकी ड्रॉ, प्रत्येक विजेता को मिलेंगे 10 लाख रुपये

नई दिल्ली, साहस समाचार।



इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट की ओर से दिल्ली-एनसीआर के ग्राहकों के लिए आयोजित 50 लाख रुपये के मेगा फेस्टिव ऑफर का ग्रैंड फिनाले ड्रॉ गुरुवार को आयोजित किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा ने इस मौके पर बंपर लकी ड्रॉ निकालकर पांच विजेताओं के नामों की घोषणा की। ड्रॉ में प्रत्येक विजेता ने 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार जीता।

ड्रॉ के तहत कूपन नंबर 26012956, 26001189, 26020053, 26181970 और 26061038 विजेता घोषित किए गए। पांचों विजेताओं को कुल 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ग्रैंड फिनाले के दौरान ग्राहकों में खासा उत्साह देखने को मिला।

इस अवसर पर अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट अपने ग्राहकों के लिए लगातार आकर्षक ऑफर और पुरस्कार लेकर आता है। उन्होंने ग्राहकों को कंपनी से खरीदारी जारी रखने और भविष्य में भी ऐसे रोमांचक ऑफर्स का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के सीईओ करण बजाज ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में कम समय में कंपनी को ग्राहकों का अच्छा समर्थन और विश्वास मिला है। 50 लाख रुपये के बंपर ड्रॉ का आयोजन ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाने की पहल है। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि कंपनी भविष्य में भी ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर और पुरस्कार योजनाएं जारी रखेगी।

बाल विवाह कुरीति की रोकथाम में सामूहिक एकजुटता पर जोर

गुरुग्राम,एजेंसी।



बाल विवाह की सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक कर इस कुरीति की रोकथाम में सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया गया।100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के आयोजित कार्यक्रम में दो ब्लॉकों की बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा देवी ने विशेष रूप से भाग लेते हुए बाल विवाह की रोकथाम और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जागरूक किया। जिला बाल संरक्षण इकाई से सुप्रिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी मुनेश व अन्नू, गुरुग्राम ब्लॉक के सरपंच अधिकारी हरिओम समेत शिक्षा विभाग और बीडीओ कार्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं एमडीडी इंडिया से निशिकांत व काउंसलर रुक्मणी शर्मा तथा शक्ति वाहिनी की टीम ने भी जागरूकता गतिविधियों में योगदान दिया।

उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने और अपने-अपने क्षेत्रों में इसकी रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 26 नवंबर को एमडीडी इंडिया की टीम ने रात्रि के समय विभिन्न गांवों का दौरा कर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का संदेश दिया और भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।

102 करोड़ से सोहना के दस गांवों में जलापूर्ति होगी

सोहना,एजेंसी।

जन स्वास्थ्य विभाग नगर परिषद के 10 गांवों समेत शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट की समस्या का समाधान अमृत दो योजना के तहत करेगा। विभाग की 102 करोड़ रुपये की योजना को उच्चाधिकारियों की ओर से मंजूरी दी गई है। विभाग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

योजना पर विभाग द्वारा 102 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर परिषद के गांव लोहटकी, सिरसका, बालूदा, लाखूवास, रामनगर की ढाणी, सांप की नंगली, रायसीना, धुनेला, खाईका और बेरका के हर घर को पेयजल की आपूर्ति दी जाएगी। इसमें नई पेयजल आपूर्ति की लाइन बिछाने के अलावा जिन गांवों में बूस्टर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध है, वहां बूस्टर बनाएं जाएंगे।

घर के बाहर फायरिंग कर ईंट-पत्थर बरसाए

पलवल,एजेंसी।

चांदहट गांव में पुरानी रंजिश या किसी विवाद को लेकर एक परिवार पर अवैध हथियारों से फायरिंग करने और ईंट-पत्थर बरसाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई। इस दौरान एक युवक के सिर में ईंट लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चांदहट थाना प्रभारी अश्वनी कुमार के अनुसार, चांदहट गांव निवासी महेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार की शाम करीब साढ़े छह बजे वह अपने घर पर था।

इसी दौरान धर्मपाल उर्फ पाली, सैलेंद्र उर्फ सैलू, सरजीत, सुनील, मन्क्की, सुन्दर समेत अन्य लोग अवैध हथियार लेकर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए ईंट-पत्थर भी बरसाए।

प्लॉट पर निर्माण कार्य कर रहे युवक के साथ गाली गलौज काम रुकवाया

लोनी,एजेंसी।

लोनी थाना क्षेत्र में प्लॉट पर निर्माण कार्य के रहे युवक के साथ गांव के कुछ लोगों ने गली गलौज कर कार्य रुकवा दिया। आरोप है कि नायब तहसीलदार और लेखपाल की निशानदेही के बावजूद आरोपियों ने प्लॉट पर काम करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लोनी थाना क्षेत्र की बादशाहपुर सिरोली गांव में इंद्रपाल रहते हैं। उन्होंने बताया कि खसरा नंबर 1303 में करीब सात सौ वर्ग गज का प्लॉट है।

उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार और लेखपाल ने छह जनवरी 2026 में निशानदेही कर दी थी। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को वह प्लॉट का निर्माण कर करने गए थे। इस दौरान गांव में रहने वाले सागर, सचिन, रमेश, शिवम, नितिन अपने अन्य अज्ञात साथी के साथ मौके पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए प्लॉट पर निर्माण कार्य करने से रोक दिया। आरोपियों ने प्लॉट पर निर्माण कार्य करने पर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की तो आरोपी मौके से फरार हो गए।

उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और प्लाट पर निर्माण कार्य कराए जाने के लिए सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। सहायक पुलिस आयुक्त ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पांच नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा गुरुग्राम के छह मोर्चों के जिलाध्यक्ष नियुक्त

गुरुग्राम,एजेंसी।



भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा गुरुग्राम के छह मोर्चों के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। इनके अंतर्गत युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, ओबीसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष पीयूष सैनी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष विशिका जैन, किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष मुकेश जैलदार, अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष नरेश नीमवाल, अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष हर्ष जैन को नियुक्त किया गया है।

भाजपा गुरुग्राम जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने सभी नवनियुक्त मोर्चा जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व, संगठनात्मक कौशल, निष्ठा एवं समर्पण से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी तथा जमीनी स्तर पर संगठन और अधिक सुदृढ़ होगा। जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, अंत्योदय और जनसेवा के सिद्धांतों पर आधारित विचारधारा एवं कार्यकर्ता प्रधान संगठन है। भाजपा में पद प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के दर्शन को आत्मसात करते हुए संगठन की विचारधारा, रीति-नीति तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि भाजपा के सभी मोर्चे संगठन की मजबूत आधारशिला होने के साथ-साथ समाज और संगठन के बीच महत्वपूर्ण सेतु हैं।

संगठन विस्तार, कार्यकर्ता निर्माण, बूथ सशक्तिकरण एवं जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करें। भाजपा गुरुग्राम जिला मीडिया प्रभारी अजय दुआ ने कहा कि नवनियुक्त मोर्चा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा की वास्तविक शक्ति उसके कर्मठ, समर्पित एवं विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष अपने नेतृत्व एवं कार्यकुशलता से संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेंगे और जनसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाएंगे।

सड़क निर्माण का आश्वासन मिलने के बाद वकीलों का धरना स्थागित

मोदीनगर,एजेंसी।

मोदीनगर तहसील परिसर में जर्जर सड़क ,क्षतिग्रस्त शौचालय का निर्माण व गंदगी से निजात दिलाने की मांग को लेकर वकीलों का धरना उपजिलाधिकारी का आश्वासन मिलने के बाद शुक्रवार को खत्म हो गया। जल्द ही सड़क व शौचालय निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजीव चिकारा कई अधिवक्ताओं के साथ तीन दिन से उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे है।

एडवोकेट संजीव चिकारा ने बताया कि वर्षों से तहसील मुख्यालय की सड़के जर्जर अवस्था में है। बरसात में यहां भारी जलभराव हो जाता है। इसके अलावा तहसील परिसर में जगह जगह गंदगी पसरी रहती है शौचालय क्षतिग्रस्त। उपजिलाधिकारी कोमल पंवार व नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी शुक्रवार दोपहर दो बजे धरनास्थल पर पहुंचे और वकीलों से वार्ता की। उपजिलाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर क्षतिग्रस्त शौचालय ठीक करने व एक माह के अंदर सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया।

इसके अलावा तहसील परिसर में गंदगी से भी निजात दिलाने की बात कहीं गई। इसके बाद अधिवक्ताओं के धरना स्थागित कर दिया। उनका कहना है कि यदि तय समय में मांग पूरी ना हुई तो फिर से धरना शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष उत्तम त्यागी, पुनीत चौधरी, अनिल चौधरी,परमवीर राठी,आशीष कुमार,सुरेंद्र कुमार सहित अन्य वकील मौजूद रहे।

फोर्टिस अस्पताल के दो डॉक्टरों की डिग्री जांच के घेरे में

नई दिल्ली,साहस समाचार।



नवजात शिशुओं के उपचार में विशेषज्ञता का दावा करने वाले फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग के दो डाक्टरों की शैक्षणिक योग्यताओं पर गंभीर सवाल उठे हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की संयुक्त जांच में दोनों डॉक्टरों को भारत में संबंधित विशेषज्ञ के रूप में पंजीकरण और कार्य करने के लिए आवश्यक योग्यताओं के मानकों पर खरा नहीं पाया गया है।

जांच समिति ने एक डाक्टर की अतिरिक्त योग्यता को दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के पंजीकरण से हटाने की सिफारिश की है, जबकि दूसरे की डिग्री को मान्यता प्राप्त अतिरिक्त विशेषज्ञ योग्यता नहीं माना है। 13 नवंबर को तैयार जांच रिपोर्ट 18 नवंबर को एनएमसी के हलफनामे के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई।

यह मामला अगस्त 2017 में फोर्टिस अस्पताल में जन्मे एक बच्चे के उपचार से जुड़ा है। बच्चे की मां सपना जैन ने आरोप लगाया था कि अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही और मेडिकल रिकार्ड में गड़बड़ी के कारण उनके बेटे को गंभीर हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हुई।

उसे सेरेब्रल पाल्सी, मिर्गी और वेस्ट सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्याएं हो गईं। हालांकि, वर्ष 2019 में डीएमसी की अनुशासनात्मक जांच में चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप साबित नहीं पाया गया था। इसके बाद डाक्टरों की विशेषज्ञता और पंजीकरण का मुद्दा अलग से उठा।

इस मामले की जांच में डा. विवेक जैन की ब्रिटेन से प्राप्त एमआरसीपीसीएच (मेम्बरशिप आफ द रायल कालेज आफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ) योग्यता की विशेषज्ञ पंजीकरण के लिए पात्रता पर सवाल उठाए गए। उनके पास प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाणपत्र (सीसीटी) नहीं था और वह ब्रिटेन के विशेषज्ञ रजिस्टर में भी पंजीकृत नहीं थे। उनकी एमआरसीपीसीएच योग्यता वर्ष 2016 में डीएमसी में अतिरिक्त योग्यता के रूप में दर्ज की गई थी। जांच समिति ने इस अतिरिक्त योग्यता को पंजीकरण से हटाने की सिफारिश की है। इसका अर्थ उनका पूरा मेडिकल पंजीकरण रद होना नहीं है। दूसरे डाक्टर डा. अखिलेश सिंह के मामले में चाइल्ड हेल्थ में डिप्लोमा की मान्यता पर सवाल उठे। यह डिप्लोमा कोलकाता के इंडियन कालेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से प्राप्त किया गया था। जांच में इसे भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) अथवा एनएमसी से मान्यता प्राप्त अतिरिक्त विशेषज्ञ योग्यता नहीं माना गया। डीएमसी के रिकार्ड के अनुसार उनका पंजीकरण एमबीबीएस के आधार पर है। इस डिप्लोमा के आधार पर उन्हें विशेषज्ञ के रूप में पंजीकरण की पात्रता नहीं मिलती।

एनएमसी को दिए जवाब में फोर्टिस अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि डा. अखिलेश सिंह योग्य सलाहकारों की निगरानी में बाल चिकित्सा टीम की सहायता करते थे और स्वतंत्र रूप से विशेषज्ञ के तौर पर उपचार नहीं करते थे। अस्पताल ने यह भी कहा कि डा. विवेक जैन को वरिष्ठ निदेशक और यूनिट प्रमुख का पद देना आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा था। अस्पताल ने मामला न्यायाधीन बताते हुए टिप्पणी करने से इन्कार किया।

मामले में 23 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यताओं की जांच के लिए संबंधित चिकित्सा नियामकों से जवाब मांगा था। मई 2025 में डीएमसी ने अंतरिम राय देते हुए दोनों डाक्टरों को नवजात शिशु विशेषज्ञ (नियोनेटोलाजिस्ट) बताने और सुपर स्पेशियलिस्ट के रूप में कार्य करने से परहेज करने को कहा था। इसके बाद 29 मई 2026 को हाई कोर्ट ने एनएमसी और डीजीएचएस को संयुक्त जांच कर आठ सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। रिपोर्ट दाखिल नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर हुई।

जेपी विशटाउन से जुड़ी परियोजनाओं की जांच 15 दिसंबर तक पूरी होगी

नोएडा,एजेंसी।



जेपी विशटाउन से जुड़ी परियोजनाओं की जांच अब 15 दिसंबर तक पूरी होगी। शासन ने जांच पूरी करने के लिए मांगे गए अतिरिक्त समय को मंजूरी दे दी है। पहले यह जांच इसी महीने पूरी करनी थी। इस बीच जांच समिति एक बार फिर से दो बार जाकर परियोजना स्थल पर जांच करेगी। खरीदारों की शिकायत पर शासन ने प्राधिकरण के ओएसडी संतोष कुमार की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति गठित की थी। इसमें नोएडा, ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी शामिल थे। शासन के निर्देश पर यह जांच इस साल सितंबर महीने में शुरू की गई थी।

जांच शुरू करने के बाद समिति ने मौके पर जाकर खरीदारों की शिकायतों का ब्योरा इकट्ठा किया था। काफी संख्या में खरीदारों ने प्राधिकरण दफ्तर पहुंचकर भी जानकारी दी थी। इसके अलावा विशटाउन परियोजनाओं का काम कर रही सुरक्षा कंपनी से परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट और तीन हजार करोड़ रुपये कहां-कहां खर्च किए, इसका ब्योरा मांगा था। अब तक सुरक्षा ने समिति को जानकारी दी है लेकिन अब भी कुछ जानकारी नहीं दी है। इस बारे में जांच समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि 15 दिसंबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।गौरतलब है कि जेपी विशटाउन का निर्माण जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की ओर से किया गया था।

परियोजना पूरी न होने और अन्य दिक्कतों के चलते मामला एनसीएलटी में चला गया। इसके बाद एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत रिजोल्यूशन प्लान के तहत काम कराने का जिम्मा सुरक्षा रियल्टी एजेंसी को दिया गया। बताया जाता है कि सुरक्षा रियल्टी द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है। जेपी विशटाउन निवासी आशीष की ओर से शासन में 10 अगस्त 2026 को इस बारे में शिकायत की गई थी।

RNI.No DLHIN/25/A2841

स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मै. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

दिल्ली की सड़कों को साफ करेंगीं नई स्वीपिंग मशीनें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।

नई दिल्ली,साहस समाचार।



दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़कों से उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए सरकार ने सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया है। शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों और 9 सपोर्ट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इन मशीनों के जरिए राजधानी की सड़कों से धूल और बारीक कणों को हटाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, पार्षद रजनीकांत सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बेहतर सफाई व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सरकार अब प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर एक साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें सड़कों पर जमा बारीक धूल और अन्य कणों को एकत्र करेंगी, जिससे उनके दोबारा हवा में उड़ने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, दिल्ली में पहले 66 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध थीं। अब 10 नई मशीनों के शामिल होने से इनकी संख्या बढ़कर 76 हो गई है। इसके अलावा सरकार ने 70 और मशीनों का ऑर्डर दिया है। इनकी आपूर्ति होने के बाद सड़कों की सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। नई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों में धूल और बारीक कणों को इकट्ठा करने के लिए विशेष सिस्टम लगाया गया है। इनके कामकाज की निगरानी भी तकनीकी माध्यम से की जा सकेगी। मशीनों ने कितने किलोमीटर सड़क की सफाई की और कितने घंटे काम किया, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

इससे उनकी कार्यक्षमता और वास्तविक उपयोग का आकलन किया जा सकेगा। सफाई अभियान में 9 सपोर्ट वाहन भी शामिल किए गए हैं। ये वाहन स्वीपिंग मशीनों को पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। खास बात यह है कि मशीनों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ अगले 10 वर्षों तक रखरखाव की व्यवस्था भी टेंडर में शामिल की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल मशीनें खरीदना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका नियमित और प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इसके लिए विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके जरिए मशीनों की निर्धारित कार्यक्षमता, तय किलोमीटर के अनुसार सफाई और एकत्र की गई धूल की मात्रा पर नजर रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के साथ कूड़े और कचरे के बेहतर प्रबंधन पर भी काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य रोजाना निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण करना और शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोग लंबे समय से कूड़े के पहाड़ और गंदगी की समस्या का सामना कर रहे हैं।

सरकार वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं, महापौर प्रवेश वाही ने उम्मीद जताई कि नई और प्रस्तावित मशीनों के जरिए सड़कों की सफाई व्यवस्था आधुनिक होगी और धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

बात मुद्दे की



आलोक गौड़

संविधान से इतना परहेज क्यों मोदी जी?

नई दिल्ली। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने संविधान के सामने सिर झुकाया। संविधान की खूबियां गिनाईं, संविधान निर्माताओं को याद किया और लोकतंत्र की ताकत का बखान किया। लेकिन इस रस्म अदायगी के अगले ही दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाकर एक बार फिर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। इस पर तो देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति है। सवाल यह है कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार आखिर करना क्या चाहती है?

महिला आरक्षण कानून 2023 में ही संसद से पारित हो चुका है। फिर उसे लागू करने के बजाय परिसीमन और जनगणना की शर्तों में क्यों उलझा दिया गया? अब लोकसभा की सीटें 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात हो रही है। इसके साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या सरकार देश को यह भरोसा दिला सकती है कि इस पूरी कवायद के पीछे केवल महिलाओं को उनका अधिकार देने की मंशा है? अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष को विश्वास में लेने से परहेज क्यों?देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस प्रस्तावित संविधान संशोधन को लेकर जो आशंकाएं जताई हैं, वे बेहद गंभीर हैं। उनका मानना है कि इसके जरिए देश में बचे-खुचे लोकतांत्रिक ढांचे को भी कमजोर करने का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने परिसीमन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि आयोग में केवल सरकार की पसंद के लोग न हों, बल्कि विपक्ष की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। आखिर इसमें गलत क्या है? देश के चुनावी नक्शे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का फैसला करने वाली संस्था पर सभी को भरोसा होना चाहिए या नहीं?

मोदी सरकार से सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसे हर महत्वपूर्ण फैसले में विपक्ष को साथ लेकर चलने में परेशानी क्यों होती है? क्या विपक्ष को केवल इसलिए नजरअंदाज किया जाएगा क्योंकि उसके पास सरकार चलाने का बहुमत नहीं है? क्या संसद में बहुमत मिल जाने का मतलब यह है कि सरकार देश के हर संवैधानिक संस्थान और व्यवस्था को अपनी मर्जी से चलाने के लिए स्वतंत्र हो गई है?

परिसीमन कोई छोटा-मोटा प्रशासनिक फैसला नहीं है। इससे देश की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया में उन राज्यों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहतर काम किया है। तमिलनाडु सहित कई राज्यों की आशंकाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज सरकार कह रही है कि राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी बरकरार रखने का प्रस्ताव है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में राज्यों और विपक्ष को पहले भरोसे में क्यों नहीं लिया गया?

मोदी सरकार की राजनीति का एक तरीका लगातार दिखाई देता है। किसी भी बड़े फैसले को ऐसे पेश किया जाता है कि उसका विरोध करने वाला व्यक्ति या राजनीतिक दल देशहित के खिलाफ खड़ा दिखाई देने लगे। अब महिला आरक्षण का मामला है। कौन महिलाओं को उनका अधिकार देने का विरोध करेगा? लेकिन महिला आरक्षण का समर्थन करने का मतलब यह तो नहीं कि परिसीमन के नाम पर सरकार जो भी प्रस्ताव लेकर आए, उस पर आंख बंद करके मुहर लगा दी जाए। महिलाओं को आरक्षण चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हर सवाल को दबा देना जरूरी है?

यह भी समझना होगा कि संविधान केवल सरकार बनाने और चलाने का रास्ता नहीं बताता, बल्कि सरकार की ताकत पर सीमाएं भी लगाता है। संविधान सरकार को बहुमत के आधार पर मनमानी करने का लाइसेंस नहीं देता। संसद में विपक्ष की मौजूदगी केवल संख्या पूरी करने के लिए नहीं है। उसका काम सरकार से सवाल पूछना, गलतियों की ओर ध्यान दिलाना और जनता के हितों की रक्षा करना है। अगर सरकार विपक्ष की हर आपत्ति को राजनीतिक विरोध बताकर खारिज कर देगी तो फिर लोकतंत्र में संवाद और सहमति का मतलब ही क्या रह जाएगा?

मोदी जी, संविधान दिवस पर संविधान के प्रति सम्मान जताना अच्छी बात है, लेकिन संविधान का सम्मान केवल भाषणों से नहीं होता। उसके लिए सरकार को अपने व्यवहार में भी लोकतांत्रिक मर्यादा दिखानी पड़ती है। महिला आरक्षण को लेकर देश को गुमराह करने के बजाय सरकार को साफ-साफ बताना चाहिए कि परिसीमन की इतनी जल्दी क्यों है और इस पूरी प्रक्रिया में विपक्ष की भूमिका क्या होगी?

आखिर देश यह जानना चाहता है कि सरकार महिलाओं को अधिकार देना चाहती है या महिला आरक्षण के बहाने देश की राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा बदलाव करना चाहती है जिसका दूरगामी असर पड़ेगा? संविधान दिवस पर नमन और अगले दिन इतने बड़े संवैधानिक बदलाव पर एकतरफा फैसला लेने की कोशिश के बीच का अंतर देश देख रहा है। सवाल पूछना विपक्ष का ही नहीं, हर जागरूक नागरिक का अधिकार है।

अगले माह से आम नागरिकों के लिए खुलेगा पूर्व सीएम आवास

वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करवाकर लोग इस आवास को देखने जा सकेंगे।

नई दिल्ली,साहस समाचार।



दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन सरकारी आवास को अगले माह से नागरिकों को दिखाने के लिए खोल दिया जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करवाकर लोग इस आवास को देखने जा सकेंगे। इसके लिए 20 से 25 रुपये की टिकट रखी जा सकती है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया के साथ इस सरकारी आवास का भ्रमण किया और उस पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये के सामान की जानकारी दी।

प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि इस आलीशान घर को बनवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने लगभग 58 करोड़ रुपये खर्च किए। इस मकान में न केवल कीमती सोफे बल्कि डाइनिंग टेबल, पर्दे, कुर्सी, पलंग, अलमारी, टीवी, लैंप, कारपेट, झूमर आदि लगाए गए हैं। यहां भूतल से खाना पहली या दूसरी मंजिल तक भेजने के लिए लिफ्ट लगी है। दूसरी मंजिल पर 22 लाख रुपये की लागत से शानदार जिम जबकि 32 लाख रुपये का वेलनेस रूम बनाया गया।

इसमें जकूजी, मसाज के लिए सीट, सॉना एवं स्टीम बाथ कैबिन शामिल है। उन्होंने कहा कि इस मकान में भूतल से दूसरी मंजिल तक करोड़ों रुपये केवल साज-सज्जा पर खर्च किए गए हैं।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के शासन में विकास के नाम पर जनता को केवल खोखले वादे दिए और वह अब पंजाब को भी उसी राह पर ले जा रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के तत्कालीन सरकारी आवास को लेकर कहा कि दिल्लीवासी लंबे समय से उस भव्य निर्माण की सच्चाई देखना चाहते थे।

अब पंजाब की जनता को भी इसे देखना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि आम आदमी पार्टी की वास्तविक प्राथमिकताएं क्या रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करदाताओं की मेहनत की कमाई को बुनियादी विकास और जनकल्याण में लगाने के बजाय निजी विलासिता, विज्ञापनों और राजनीतिक प्रचार पर खर्च किया गया।

जीवन प्रमाणपत्र जल्द जमा करें, विलंबित आयकर रिटर्न भी तुरंत भरें

नई दिल्ली,साहस समाचार।

करदाताओं के लिए दिसंबर का महीना काफी अहम रहने वाला है। उन्हें साल खत्म होने से पहले आयकर से जुड़े कई जरूरी काम निपटाने होंगे। जो करदाता 31 जुलाई 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे , वे 31 दिसंबर 2026 तक देरी से रिटर्न भर सकते हैं। इसके अलावा 31 दिसंबर 2026 तक पात्र करदाता विदेश में मौजूद अपनी संपत्ति या वहां से हुई कमाई की जानकारी दे सकते हैं। समय-सीमा के भीतर ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना लग सकता है।

वहीं, पेंशनभोगियों को भी एक दिसंबर से पहले अपना वार्षिक या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर दिसंबर से नियमित मासिक पेंशन पाने में दिक्कत आ सकती है। पेंशन पाने वाले लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहे, इसके लिए उन्हें एक दिसंबर से पहले अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा भी उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे जमा किया जा सकता है।

इसके अलावा बैंक या संबंधित पेंशन कार्यालय में जाकर भी प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प है। तय समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर दिसंबर से पेंशन मिलने में देरी या रुकावट आ सकती है। इसलिए पेंशनभोगियों को समय रहते यह काम पूरा कर लेना चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार में बदलाव कराने के लिए शुल्क तय किया है। नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पते में बदलाव बायोमेट्रिक जानकारी के साथ कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं, अलग से बदलाव कराने पर 75 रुपये देने होंगे। हालांकि, आधार ऐप के जरिए ईमेल पता 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त में अपडेट कराया जा सकता है। इसके अलावा, आधार में पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की सुविधा 14 जून 2027 तक मुफ्त रहेगी। इसके लिए आधार की वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। वहीं, आधार केंद्र पर जाकर दस्तावेज जमा कराने पर 75 रुपये शुल्क देना होगा।

जिन करदाताओं ने 31 जुलाई 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे 31 दिसंबर 2026 तक देरी से रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि, यह मौका तभी तक मिलेगा, जब तक आयकर विभाग की ओर से आकलन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो। देरी से रिटर्न भरने पर जुर्माना भी देना होगा। पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को 1,000 रुपये और इससे अधिक आय वालों को 5,000 रुपये शुल्क देना पड़ सकता है।

बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली के तीन इलाकों की हवा

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित बनी हुई है। शुक्रवार को राजधानी के तीन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। अगले दो दिनों के दौरान भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता पूरी तरह साफ होने की उम्मीद नहीं है। मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते दिल्ली में अक्तूबर में इस बार वायु गुणवत्ता काफी हद तक साफ-सुथरी रही थी।

हालांकि, नवंबर में लगातार वायु गुणवत्ता का स्तर खराब या बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। खासतौर पर दिवाली के आसपास दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रहा। बाद में हवा की गति बढ़ने और गर्म मौसम की वजह से प्रदूषण के स्तर में हल्की कमी जरूर आई, लेकिन हवा अभी भी सांस लेने लायक नहीं है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शुक्रवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 226 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 224 अंक पर था। यानी 24 घंटे में इसमें दो अंकों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, दिल्ली के तीन इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। इनमें सीआरआरआई मथुरा रोड, डीटीयू और आईजीआई एयरपोर्ट के इलाके शामिल हैं।

मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 2.5 का स्तर 60 और पीएम 10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। जबकि, दिल्ली-एनसीआर की हवा में गुरुवार रात 12 बजे पीएम 2.5 का स्तर 100.36 और पीएम 10 का स्तर 198.72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।

दिल्ली विस अध्यक्ष ने संविधान दिवस फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

नई दिल्ली,साहस समाचार।



दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में संविधान दिवस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे गणराज्य की जीवंत आत्मा है, जिसका निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता, त्याग और कलात्मक विरासत से हुआ है। इस प्रदर्शनी का आयोजन अधिवक्ता परिषद, दिल्ली प्रांत (पटियाला हाउस कोर्ट इकाई) द्वारा नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सहयोग से किया गया।

उद्घाटन समारोह में विधिक समुदाय के सदस्य, विद्यार्थी एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। औपचारिक उद्घाटन के बाद विजेंद्र गुप्ता ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शित दुर्लभ ऐतिहासिक चित्रों एवं विभिन्न दृश्य सामग्रियों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा आयोजकों से इस प्रदर्शनी में समाहित ऐतिहासिक तथ्यों और उनके महत्व पर चर्चा की।

गुप्ता ने अधिवक्ता परिषद और नई दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल के माध्यम से भारत के लोकतंत्र की आधारशिला से जुड़े इतिहास को विधिक क्षेत्र के पेशेवरों, युवा कानून विद्यार्थियों और आम नागरिकों तक सीधे पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संविधान सभा की बहसों, आदर्शों और संविधान की मूल पांडुलिपि के पीछे निहित कलात्मक उत्कृष्टता का पुनरावलोकन नागरिक दायित्व की भावना को गहरा करता है तथा दैनिक सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाता है। गुप्ता ने संविधान सभा की चर्चाओं की कालजयी प्रासंगिकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा में विधिक समुदाय के निरंतर योगदान को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि दुर्लभ अभिलेखीय तस्वीरों, संविधान की मूल पांडुलिपि में की गई कलात्मक चित्रकारी और उन गुमनाम अग्रदूतों की प्रेरक कहानियों को एक साथ प्रस्तुत करना भारत के संवैधानिक इतिहास और भावी पीढ़ियों के बीच एक अमूल्य सेतु का कार्य करता है।

भाजपा सरकार के महिला सुरक्षा के दावों की खोली पोल: देवेन्द्र यादव

नई दिल्ली, साहस समाचार।



दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के दिशा निर्देश पर आज प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ राव ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में दिल्ली में लगातार बढ़ रहे यौन शोषण के चिंतनशील मामलों पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया।

श्रीमती प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के भारत नगर थाना के संगम पार्क स्थित पीडब्लूडी के पार्क में 24 नवम्बर को दिन के उजाले में प्रातः अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति द्वारा 10 वर्ष की छोटी बच्ची को लालच देकर बहला फुसला कर उसका रेप करने की कोशिश करता है, जो समाज के लिए चिंताजनक है।

बच्ची की आवाज सुनकर लोगों ने राजेश कुमार नाम व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेजा, जो पहले भी एक नाबालिग से यौन अपराध से जुड़े पोस्को मामलें में दोषी होने के 7-8 साल की सजा काटकर कुछ महीने पहले ही रिहा हुआ था। श्रीमती प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि देश की राजधानी में हर बढ़ते यौन शोषण के मामलों और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में दिल्ली में भाजपा की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता सरकार नाकाम साबित हुई है।

उन्होंने कहा कि कालका जी के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय युवती के साथ नकली पुलिस बनकर गैंगरेप करने वाले मामले के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्कों में अपराधों और आसामाजिक तत्वों की क्रियाशीलता को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का जोर शोर से प्रचार किया था।

मैं बताना चाहती हू कि भाजपा के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे का यह हशर है कि संगम पार्क क्षेत्र के पार्क में एक भी सीसीटीवी कैमरा नही था जबकि आस्था कुंज पार्क की घटना हुए लगभग 2 महीने पूरे हो चुके है। यह कोई एक दो मामले नही है हर दिन राजधानी में 4-5 पंजीकृत बलात्कार की घटनाएं दर्ज हो रही है, जो देश की राजधानी के लिए शर्मनाक है।

श्रीमती प्रियंका कक्कड़ ने कहा यह चिंताजनक है कि अक्टूबर में आई आडिट रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी के 736 पार्क है जिनमें से मात्र 16 पार्क में सीसीटीवी केमरे है, जबकि 720 पार्कों में एक भी सीसीटीवी कैमरा नही है। यही हाल दिल्ली नगर निगम का है, निगम के 15320 पार्कों में एक भी सीसीटीवी कैमरा नही है।

उन्होंने कहा कि 2022-2025 तक निगम में आम आदमी पार्टी सत्ता में थी और अब निगम भाजपा के आधीन है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारों के गैरजिम्मेदाराना रवैये और जनता की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशीलता के कारण राजधानी में लोग विशेषकर महिलाएं असुरक्षित माहौल में जी रहे है।

यहां पुलिस हर अपराधिक मामले में अपने को असहाय दिखाकर अपराध के बाद जांच करती दिखाई देती है। जिसका बड़ा कारण स्ट्रीट लाईट न होना, डार्क स्पाट बढ़ना और घोषणा तथा बजट के आवंटन के बावजूद सीसीटीवी की नकारात्मक संख्या अपराधियों के हौसले बढ़ा रहे है।

शहीद धन सिंह गुर्जर की जयंती पर ईदाते आयोग की सिफारिशें लागू करने की माँग

नई दिल्ली,साहस समाचार।



दिल्ली गण परिषद के अध्यक्ष एवं एमसीडी के पूर्व चेयरमैन एडवोकेट धर्मवीर सिंह ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद धन सिंह गुर्जर की जयंती पर उन्हें विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की आजादी में उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। शाहिद धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र दिल्ली बना और उनकी वीरता एवं संघर्ष के बदौलत चंद दिनों में ही एनसीआर को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मुक्त करा लिया गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने देश की 198 वीर जातियों को इस क्रांति का दोषी मानते हुए उन पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 लगाया दिया। इन वीर जातियों की जमीन जायदाद को जबरदस्ती छीनकर इन्हें शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं से 100 वर्षों तक वंचित रखा गया। इस समाज के लोगों को गोलियों एवं तोप से उड़ा दिया गया तथा उनके गांव को नेस्तनाबूद कर दिया गया।श्री सिंह ने कहा कि आजादी के बाद इन जातियों के उत्थान के लिए डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड फॉर द नोटिफाई, नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक कम्युनिटी का गठन 2019 में किया गया।

भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार को 18 अगस्त 2020 को पत्र भेजा गया जिसमें उपरोक्त जातियों को जाति प्रमाण पत्र देने की समय सीमा 30 दिसंबर 2020 रखी गई।परंतु इस आदेश के बाद भी अभी तक इन वीर जातियों को ना तो न्याय मिल पाया है और नहीं उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र ही निर्गत किए गए हैं।

गण परिषद के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि वह इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र डीएनटी समाज को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें जिससे केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ विमुक्त जनजातियों को मिल सके!



संपादकीय

क्या परिसीमन से बदलेगा भारत का राजनीतिक भविष्य?

देवेंद्र सिंह तोमर

भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां संसद की सीटों का गणित देश की राजनीति का भूगोल बदल सकता है। परिसीमन को लेकर संसद के विशेष सत्र और संभावित विधायी पहल की चर्चाओं ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। लोकसभा की सीटों में वृद्धि, राज्यों के प्रतिनिधित्व का नया निर्धारण और 2051 तक सीटों की सीमा जैसे सवाल अब केवल संवैधानिक विमर्श नहीं रह गए हैं, बल्कि सत्ता के भविष्य से जुड़े प्रश्न बन चुके हैं। परिसीमन का उद्देश्य लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, लेकिन इसकी प्रक्रिया यदि संतुलित नहीं हुई तो यही उद्देश्य राज्यों के बीच राजनीतिक असमानता का कारण भी बन सकता है।

परिसीमन का सीधा अर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण और आवश्यकतानुसार सीटों की संख्या में बदलाव। आबादी बढ़ने के साथ मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों लोगों के प्रतिनिधित्व का बोझ हो और किसी दूसरे क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम मतदाता हों, तो व्यवस्था में सुधार किया जाए। लोकतंत्र का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य लगभग समान होना चाहिए। इस दृष्टि से परिसीमन आवश्यक है और इसे अनिश्चितकाल तक टालना भी उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारत की परिस्थितियां केवल जनसंख्या के आंकड़ों से नहीं समझी जा सकतीं। यह देश विविध भाषाओं, संस्कृतियों, आर्थिक स्थितियों और विकास के अलग-अलग स्तरों वाला संघीय गणराज्य है। यहां राज्यों का प्रतिनिधित्व केवल आबादी का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का आधार भी है। इसलिए परिसीमन करते समय यह देखना होगा कि लोकतांत्रिक समानता और संघीय संतुलन के बीच कोई टकराव पैदा न हो।

सबसे बड़ा विवाद उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संभावित राजनीतिक संतुलन को लेकर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ने की संभावना स्वाभाविक रूप से अधिक हो सकती है। दूसरी ओर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता यह है कि जनसंख्या नियंत्रण और विकास के प्रयासों के बावजूद संसद में उनका सापेक्ष प्रभाव कम न हो जाए। यह चिंता केवल राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि भारतीय संघ की संरचना से जुड़ी है। जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की, उन्हें यदि सीटों के अनुपात में नुकसान उठाना पड़े, तो यह एक गलत संदेश होगा। क्या बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और परिवार नियोजन अपनाने वाले राज्यों को राजनीतिक रूप से कमजोर होना चाहिए? दूसरी ओर, अधिक आबादी वाले राज्यों के नागरिकों को कम प्रतिनिधित्व में रखना भी लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यही परिसीमन की सबसे कठिन चुनौती है—दोनों पक्षों के तर्क महत्वपूर्ण हैं और किसी एक को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

इस बहस का राजनीतिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लोकसभा की सीटों में बड़ी वृद्धि होने पर चुनावी रणनीतियां बदलेंगी। जिन राज्यों में सीटों की संख्या अधिक बढ़ेगी, वहां राजनीतिक दलों का ध्यान और संसाधन भी बढ़ सकते हैं। भाजपा और उसके सहयोगियों को कुछ क्षेत्रों में संभावित लाभ मिल सकता है, जबकि विपक्षी दलों को नए राजनीतिक समीकरणों के अनुरूप संगठन और उम्मीदवारों की रणनीति बदलनी होगी। हालांकि सीटों की वृद्धि अपने आप किसी दल की जीत सुनिश्चित नहीं करती। मतदाता का निर्णय, स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक नेतृत्व ही अंततः चुनाव का परिणाम तय करते हैं। परिसीमन का एक महत्वपूर्ण संबंध महिला आरक्षण से भी है। 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा है।

पंजाब : पर्दे के पीछे ऐसे बुनी गई छह साल बाद वापसी की पटकथा



सुदेश गौड़

मोदी और शाह के स्तर पर राजनीतिक सहमति बनने के बाद पार्टी संगठन को इस निर्णय के साथ खड़ा करना आवश्यक था। गठबंधन की औपचारिक घोषणा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति ने यह स्पष्ट किया कि यह किसी एक नेता का व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि भाजपा का संस्थागत राजनीतिक फैसला है।



राजनीति में किसी गठबंधन की घोषणा भले ही मंच पर दो-चार बड़े नेता करते दिखाई दें लेकिन उसके पीछे कई ऐसे चेहरे होते हैं जो महीनों तक संवाद, गणित, सर्वेक्षण, असहमतियों और राजनीतिक संभावनाओं पर काम करते हैं। पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच छह साल बाद हुआ गठबंधन इसका दिलचस्प उदाहरण है। यहां हुए राजनीतिक पुनर्मिलन के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक इच्छाशक्ति, गुजरात से उनके पुराने सहयोगी सीआर पाटिल की चुनावी रणनीति, पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की शुरुआती पहल, पंजाब से मिले जमीनी फीडबैक और कुछ ऐसे नेताओं के प्रयास हैं जिन्होंने दोनों दलों के बीच भरोसे की जमीन तैयार की। इस गठबंधन की असली कहानी पर्दे के पीछे इन्हीं काम करने वाले नायकों की है।

इस पूरी कवायद के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रहे। उन्होंने राजग के पुराने सहयोगियों को फिर साथ लाने की राजनीतिक जरूरत को समझा। हाल ही में राजग के सहयोगी दलों की एक बैठक में मोदी ने अकाली दल के दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल, शिवसेना के बाल ठाकरे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्नेहपूर्वक उल्लेख किया था। इसे पुराने सहयोगियों के प्रति सम्मान और राजनीतिक संबंधों को फिर मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा गया। इसके बाद अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात हुई। साल 2020 में गठबंधन टूटने के बाद यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी। इसने दोनों दलों के बीच जमी बर्फ पिघलाने का काम किया। मोदी ने इस मामले को केवल सीटों और सत्ता के गणित तक सीमित नहीं रखा। पंजाब की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सद्भाव, नशे की समस्या और सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा जैसे व्यापक विषय भी इस राजनीतिक पुनर्समीक्षा का हिस्सा बने। इस घटनाक्रम में सबसे उल्लेखनीय पर्दे के पीछे का नाम सीआर पाटिल का है। गुजरात की राजनीति में नरेन्द्र मोदी के साथ लंबे समय तक काम कर चुके सीआर पाटिल को पंजाब में भाजपा की चुनावी संभावनाओं का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अलग-अलग स्तरों पर जमीनी सर्वेक्षण करवाए। इनका उद्देश्य केवल भाजपा की लोकप्रियता जानना नहीं था बल्कि यह समझना भी था कि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर राजनीतिक परिणाम किस तरह बदल सकते हैं। सर्वेक्षणों से जो निष्कर्ष सामने आए, वे भाजपा नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण थे। यही वह मोड़ था जहां गठबंधन की राजनीतिक इच्छा को चुनावी आंकड़ों का आधार मिला।

अकाली दल और भाजपा के बीच रिश्ते सितंबर 2020 में कृषि कानूनों के विरोध के कारण टूट गए थे। दोनों दलों के बीच करीब 24 वर्ष पुराना गठबंधन समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 अप्रैल 2023 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने लांबी पहुंचे। यह केवल एक शोकसभा में उपस्थिति नहीं थी। साल 2020 में अलगाव के बाद दोनों दलों के नेताओं का एक साथ दिखाई देना संबंधों में नरमी का पहला सार्वजनिक संकेत बना। नड्डा की इस पहल ने यह संदेश दिया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पुराने संबंधों और सहयोगियों के प्रति सम्मान कायम है।

इस घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि चर्चाओं के अनुसार अमित शाह शुरुआत में अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। भाजपा का एक वर्ग चाहता था कि पार्टी पंजाब में अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार विकसित करे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पंजाब में अपनी स्थिति बेहतर की थी लेकिन सीआर पाटिल के सर्वेक्षण, पंजाब से मिले राजनीतिक फीडबैक और व्यापक राष्ट्रीय परिस्थितियों के आकलन ने तस्वीर बदल दी।

शाह की पंजाब यात्राओं के दौरान नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परिवारों से संवाद महत्वपूर्ण रहा। इन मुलाकातों ने पंजाब की वास्तविक समस्याओं को राजनीतिक नेतृत्व के सामने अधिक स्पष्ट किया। अंततः शाह ने गठबंधन के पक्ष में सहमति बनाई। शाह की भूमिका को केवल गठबंधन की घोषणा करने वाले नेता के रूप में नहीं बल्कि शुरुआती असहमति से अंतिम सहमति तक पहुंचे निर्णायक सूत्रधार के रूप में है।

पंजाब की राजनीति और वहां के सामाजिक समीकरणों की रवनीत सिंह बिट्टू की समझ भाजपा के लिए उपयोगी रही है। बिट्टू मानते भी हैं कि भाजपा का अकाली दल के साथ वापस आने का निर्णय पंजाब की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक पर आधारित है। जमीनी स्तर पर दोनों दलों के साथ आने की मांग महसूस की जा रही थी। बिट्टू की भूमिका को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि भाजपा को पंजाब में केवल चुनावी सर्वेक्षणों की नहीं बल्कि स्थानीय राजनीतिक मनोदशा की भी जानकारी चाहिए थी। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की नाराजगी, सिख मतदाताओं का रुख, अकाली दल की संगठनात्मक स्थिति और भाजपा के प्रति स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे विषयों पर जमीनी फीडबैक का महत्व था। पुराने गठबंधन को वापस लाने की अकाली दल की ओर से सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल सुखबीर सिंह बादल की रही। भाजपा नेताओं के प्रयासों के साथ अकाली दल की ओर से भी इस गठबंधन को संभव बनाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी थी। सुखबीर सिंह बादल ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके बाद दोनों दलों के बीच बातचीत आगे बढ़ी।

सुखबीर के सामने भी आसान स्थिति नहीं थी। कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा से अलग होने के बाद अकाली दल ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखने की कोशिश की लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल तीन सीटों पर सिमट गई। पार्टी के लिए पुराने राजनीतिक आधार को वापस पाना जरूरी था। भाजपा के संगठनात्मक संसाधनों और राष्ट्रीय राजनीतिक पहुंच का लाभ भी महत्वपूर्ण था। सुखबीर बादल ने 24 नवंबर को गठबंधन को केवल राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि पंजाब के हित में भावनात्मक संबंधों की पुनर्स्थापना बताया।

मोदी और शाह के स्तर पर राजनीतिक सहमति बनने के बाद पार्टी संगठन को इस निर्णय के साथ खड़ा करना आवश्यक था। गठबंधन की औपचारिक घोषणा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति ने यह स्पष्ट किया कि यह किसी एक नेता का व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि भाजपा का संस्थागत राजनीतिक फैसला है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों दलों के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी। इस तरह पर्दे के पीछे की राजनीतिक कवायद को औपचारिक संगठनात्मक स्वीकृति दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

राजस्थानः सत्ता में महिलाओं की भागीदारी के नए संकेत



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा



महिलाओं की सत्ता में भागीदारी से यह भी माना जा सकता है कि महिलाएं जमीनी हकीकत से अधिक जुड़ी होती है, ऐसे में पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान में सार्थक और सकारात्मक परिणाम की आशा की जा सकती है। माना जा रहा है कि युवा और शिक्षित महिला नेतृत्व का फोकस शुद्ध पेयजल से लेकर बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी और स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझने और उनके निराकरण में अधिक सकारात्मकता आएगी।

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को लेकर किसका पलड़ा भारी या कमजोर रहा या चुनाव परिणामों का राजस्थान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह राजनीति विज्ञों के बीच अलग विचार का मुद्दा हो सकता है पर राजस्थान से जिला प्रमुखों के चुनाव परिणाम से जिस तरह सत्ता में भागीदारी में सशक्तिकरण उभर का आया है वह एक सकारात्मक संकेत है। राजस्थान के नागौर से पंचायतीराज का बिगुल बजा था और आज जिला प्रमुखों के 70 फीसदी महिलाओं की हिस्सेदारी की नई बयार देखने को मिल रही है। सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर राजस्थान से सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। राजस्थान में जिला प्रमुखों के चुनाव परिणाम न केवल चौंकाने वाले हैं अपितु आने वाले समय में महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ने की दिशा में बढ़ता कदम माना जा सकता है। राजस्थान में 37 जिला परिषदों के परिणामों में 26 जिला परिषदों में जिला प्रमुख के पद पर महिलाएं चुनी गई है। इसमें भी खास बात यह है कि सुदूर रेगिस्तानी जिले जैसलमेर से महज 21 साल और एक माह की आयु की संतोष कुमारी जिला प्रमुख चुनी गई है तो 21 वर्ष और 4 माह की वर्षा झाला झालावाड़ की जिला प्रमुख चुनी गई है।

सबसे अच्छी बात यह है कि जिला प्रमुख बनने वाली महिलाओं में अधिकांश जहां युवा हैं तो दूसरी ओर अच्छी पढ़ी-लिखी महिलाएं जिला प्रमुख बनी है। देखा जाए तो महिलाओं में भी राजस्थान में शिक्षित और युवा महिला नेतृत्व उभर कर आया है। इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है।

महिलाओं की सत्ता में भागीदारी से यह भी माना जा सकता है कि महिलाएं जमीनी हकीकत से अधिक जुड़ी होती है, ऐसे में पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान में सार्थक और सकारात्मक परिणाम की आशा की जा सकती है। माना जा रहा है कि युवा और शिक्षित महिला नेतृत्व का फोकस शुद्ध पेयजल से लेकर बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी और स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझने और उनके निराकरण में अधिक सकारात्मकता आएगी। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर भी एक हद तक रोक संभव हो पाएगी तो महिलाएं नए जोश और नई ऊर्जा से काम करते हुए परिणाम देने का प्रयास करेंगी। कुल मिलाकर कार्य व्यवस्था में बदलाव की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता।

महिलाओं की सत्ता में दमदार भागीदारी के बावजूद संभावना जताते हुए सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह पंचायतों में सरपंच पति, प्रधान पति या पंच पति का दौर चला था, क्या उसी तरह प्रमुख पति के रुप में राजनीतिक सक्रियता दिखेगी। सच्चे मायने में महिला जिला प्रमुख ही सत्ता की भागीदार बने और निर्णय जिला प्रमुख का ही रहे, जिला प्रमुख पति आदि का नहीं। कहने का अर्थ यह है कि महिलाओं को निर्णय क्षमता विकसित करनी होगी और प्रशासन में अपनी निर्णय क्षमता और कार्यशैली की छाप छोड़ने की चुनौती महिला जिला प्रमुखों के सामने होगी। राज्य सरकार को भी नई जिला प्रमुखों आदि के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रम व्यापक व निरंतरता के साथ आयोजित करने होंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी सच्चे मायने में उभरकर आ सके। सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वैश्विक औसत 27.5 फीसदी है। 30 देशों में राष्ट्राध्यक्ष महिला है तो दुनिया के केवल 8 देश ही ऐसे हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी से अधिक है। रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टारिका, बोलिविया, मैक्सिको, एंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। इस समय दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां सत्ता में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

पिछले चुनाव में सरकार बनाने में महिलाएं निर्णायक भूमिका में रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 14 राज्यों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 19 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो यह भी साफ हो जाता है कि लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं को केन्द्र में रखकर चुनाव घोषणापत्र बनाये और महिलाओं को किसी भी नाम से योजना रखते हुए एक निश्चित राशि देने की बात प्रमुखता से की।

राजनीतिक पार्टियां कहने को कुछ भी कहे या महिलाओं को आगे लाने की कितनी भी बात करें पर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी तक बढ़ नहीं पाई है। महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत जहां 27.5 प्रतिशत है, वहीं हमारे देश में अभी तक यह 14-15 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। रोचक बात यह है कि साल 2009 की 15वीं लोकसभा के पहले तक हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दहाई की संख्या में भी नहीं पहुंचा था। 15वीं लोकसभा में पहली बार 10.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो सका। हालांकि साल 1977 में आपातकाल के ठीक बाद की लोकसभा में सबसे कम भागीदारी केवल 3.5 प्रतिशत ही रह गई थी। पर 1977 के हालात अलग थे और उनको अलग करके देखा जाना चाहिए। उस समय आपात्काल के बाद की स्थितियां थी। 18वी लोकसभा में 17 वीं लोकसभा की तुलना में 3 महिला सांसद कम है। इस तरह से 17वीं लोकसभा में महिलाओं की सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत भागीदारी रही। इन सब हालातों में राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं में जिला प्रमुख की जिम्मेदारी 70 फीसदी से अधिक महिलाओं और खासतौर से युवा और शिक्षित महिलाओं के हाथ में आई है तो इससे राजनीतिक परिदृश्य के लिए शुभ और सकारात्मक संदेश माना जाना चाहिए। इसके साथ ही महिला जिला प्रमुखों से भी यह अपेक्षा रहेगी वे स्वयं निर्णय लेने और विकास में भागीदार बनने का संदेश दें।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

भारतीय खाद्य संस्कृति पर आघातों से सुप्रीम कोर्ट चिन्तित

भारत की पहचान केवल उसकी आध्यात्मिकता, विविधता और संस्कृति से नहीं, उसकी रसोई से भी होती है। हमारी रसोई में स्वाद के साथ स्वास्थ्य, ऋतु के साथ संतुलन और भोजन के साथ संस्कार जुड़े रहे हैं। दादी-नानी के हाथों का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, वह परिवार की सेहत की पहली पाठशाला था। दाल, बाजरा, ज्वार, रागी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, छाछ, अंकुरित अनाज, मसालों का संतुलित उपयोग और घर का ताजा भोजन भारतीय जीवन-पद्धति की ताकत रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारी थाली धीरे-धीरे बदल गई है। स्वाद के नाम पर बाजार ने हमारी रसोई में प्रवेश किया और सुविधा के नाम पर पैकेट ने घर की कड़ाही को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसी बदलती खाद्य संस्कृति के बीच सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश एक महत्वपूर्ण चेतावनी की तरह सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य पैकेटों पर फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबलिंग को मजबूत करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अधिक शुगर, सैचुरेटेड फैट और नमक वाले उत्पादों पर अलग-अलग स्पष्ट चेतावनी चिह्न हों। न्यायालय ने 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को प्रमुखता से दिखाने तथा 'हाई शुगर', 'हाई फैट और 'हाई साल्ट' जैसे स्पष्ट संकेत देने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है-उपभोक्ता को वह जानकारी सामने मिले, जिसे वह छोटे अक्षरों में खोजते-खोजते अक्सर छोड़ देता है।



यह फैसला केवल लेबल बदलने का फैसला नहीं है, यह उस सोच को बदलने का प्रयास है जिसमें चमकदार पैकेट देखकर भोजन की गुणवत्ता तय कर ली जाती है। आज बाजार में किसी उत्पाद का विज्ञापन उसकी पोष्टिकता से अधिक आकर्षक पैकेजिंग, स्वाद और सुविधा बेचता है। बच्चे रंगीन पैकेट से आकर्षित होते हैं, युवा त्वरित भोजन को जीवनशैली समझने लगे हैं और व्यस्त परिवारों के लिए डिब्बाबंद भोजन समय बचाने का आसान विकल्प बन गया है। समस्या तब पैदा होती है जब सुविधा धीरे-धीरे आदत और आदत बीमारी में बदल जाती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि भोजन का अर्थ बदल रहा है। भोजन कभी जीवन को पोषण देने की प्रक्रिया था, अब वह तेजी से उपभोग की वस्तु बन रहा है। अधिक नमक, अधिक चीनी और अधिक वसा हमारे स्वाद की इंद्रियों को तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन शरीर की जरूरतों को नहीं। स्वाद की जीभ छोटी अवधि की खुशी चाहती है, जबकि शरीर दीर्घकालिक संतुलन मांगता है। बाजार ने हमारी जीभ को जीतने की कोशिश की है, अब हमें अपने विवेक को जीतना होगा।

भारत जैसे देश में यह चुनौती और गंभीर है, क्योंकि यहां भोजन केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। हमारी परंपरा में 'जैसा अन्न वैसा मन' की धारणा रही है। भोजन को आयु, ऋतु, प्रकृति और श्रम के अनुरूप लेने की परंपरा थी। भारतीय रसोई में अनेक ऐसे खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें आज दुनिया 'सुपरफूड' कहकर खोज रही है। बाजरा, जौ, दालें, तिल, मूंगफली, विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां और स्थानीय खाद्य परंपराएं हमारी अपनी विरासत हैं। विडंबना यह है कि जिन खाद्य पदार्थों की ओर दुनिया स्वास्थ्य के लिए लौट रही है, हम उन्हीं को छोड़कर अत्यधिक प्रसंस्कृत और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पहल को केवल उपभोक्ता अधिकार का विषय मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसे भारतीय खाद्य संस्कृति के पुनर्जागरण के अवसर के रूप में देखना चाहिए।

सरकार की जिम्मेदारी भी यहां बहुत बड़ी है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल यह सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए कि उत्पाद खाने योग्य है, यह भी देखना होगा कि उपभोक्ता को उस उत्पाद के वास्तविक स्वास्थ्य प्रभाव की जानकारी आसानी से मिले। एफएसएसएआई को वैज्ञानिक, स्पष्ट और उपभोक्ता-केंद्रित नियम बनाने होंगे। केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं, उनका प्रभावी निरीक्षण और कठोर पालन भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इसी दिशा में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने का अवसर देता है। लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकार या अदालत की नहीं हो सकती। उपभोक्ता को भी अपनी थाली का प्रहरी बनना होगा।

भारत और सनातन एक-दूसरे के पूरक: योगी आदित्यनाथ

बलरामपुर, एजेंसी।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और सनातन धर्म को एक दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि यदि भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा और सनातन धर्म सशक्त होगा तो भारत भी समर्थ बनेगा।

उन्होंने कहा कि इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) का मंत्र हर भारतीय का संकल्प बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ यहां तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन में ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिणाम भाषणों या उपदेशों से नहीं, बल्कि पुरुषार्थ, परिश्रम और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन से आते हैं। जब छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, शिक्षक बच्चों को पारंगत करेगा, किसान खेतों में परिश्रम करेगा, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करेगा, गृहस्थ बच्चों को संस्कारित करेगा, संत जनजागरण करेगा और गोपालक गोमाता की सेवा करेगा, तभी राष्ट्र सशक्त और समर्थ बनेगा।

उन्होंने कहा कि विगत पांच हजार वर्षों से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के माध्यम से किंकर्तव्यविमूढ़ समाज को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में यह पावन कथा हर सनातन धर्मावलंबी का मार्गदर्शन करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म कृतज्ञता ज्ञापित करने की महान परंपरा का वाहक है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के पूरे 15 दिन हम अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध और तर्पण के लिए समर्पित करते हैं।

उन्होंने ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा, ''जब क्रूर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर 24 घंटे में केवल एक छोटे घड़े में पानी दिया और वह एक-एक बूंद को तरसने लगा, तब शाहजहां ने औरंगजेब को कोसते हुए कहा था कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं, जो जीते-जी बुजुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद भी वर्ष में एक बार श्राद्ध-तर्पण कर उनका स्मरण करते हैं।

मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि जब तक सनातन धर्मावलंबियों में कृतज्ञता का यह भाव बना रहेगा और हम जाति, क्षेत्र और भाषा भेद से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, तभी तक भारत सुरक्षित और अखंड बना रहेगा।

ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज के कृतित्व को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक संत का कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं होता, वह समाज, देश और धर्म के लिए जीता है। महंत महेंद्र नाथ जी ने गोरखपुर में पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में जो कुछ सीखा, उसे देवीपाटन में साकार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत महेंद्र नाथ जी ने 1994 में थारू जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास शुरू कराया, धर्मशालाएं बनवाईं, नंद महरा में स्कूल, अस्पताल, तुलसीपुर में सीबीएसई विद्यालय, मंदिर सौंदर्यीकरण, गोशाला विस्तार और निशुल्क अन्नपूर्णा भोजनालय जैसी जनसेवा की अनेक परियोजनाएं आगे बढ़ाईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिशक्ति मां भगवती की यह पौराणिक शक्तिपीठ गुरु गोरक्षनाथ से लेकर सिद्ध योगी बने पीर रतन नाथ जी महाराज (नेपाल में दांग राजघराने के राजकुमार थे) की महान परंपरा से जुड़ी है। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र पर नेपाल से पीर रतन नाथ जी की सवारी यहां आती है। समारोह में कथा व्यास संत बालक दास जी महाराज, शक्तिपीठ देवीपाटन के महंत एवं आयोजक मिथिलेश नाथ जी महाराज, कालीबाड़ी गोरखपुर के महंत रवींद्र दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के महंत राजू दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी बलरामपुर के महंत महेंद्र दास जी महाराज, हिसार (हरियाणा) से आए महंत विनोद नाथ जी महाराज, नेपाल से आए योगी नारायण नाथ आदि उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया मंचों की जवाबदेही सुनिश्चित हो: युवा कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि मेटा के खिलाफ चलाए जा रहे उसके 'डिजिटल आजादी' अभियान को लोगों का भरपूर समर्थन तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मीडिया कवरेज मिली है।

उसका यह भी कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही का होना जरूरी है।

युवा कांग्रेस ने हाल ही में अपने कई पदाधिकारियों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोक लगने के बाद यह अभियान शुरू किया। इसके तहत उसने इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा को लेकर डिजिटल दुनिया में कई सवाल उठाए और आंकड़ों के साथ इस बात को रखने का प्रयास किया कि सोशल मीडिया मंचों पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है।

संगठन के मुताबिक, 20 से 26 नवंबर के बीच 46 देशों के 106 मीडिया स्रोतों में अभियान से संबंधित खबरें और लिंक दर्ज किए गए।

युवा कांग्रेस की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 41 देशों में उसके अभियान की मीडिया कवरेज की गई। संगठन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने मेटा की 'कंटेंट मॉडरेशन' नीतियों, राजनीतिक सामग्री हटाए जाने, विपक्षी आवाजों पर कथित प्रतिबंधों और कंपनी से पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मांग से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है।

त्रिपुरा निकाय चुनावों में 72 प्रतिशत मतदान

अगरतला, एजेंसी।



त्रिपुरा में शुक्रवार को 16 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में दोपहर तीन बजे तक करीब 72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अगरतला नगर निगम (एएमसी) के कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहले ही पांच नगर निकायों में निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रदीप कुमार चक्रवर्ती ने बताया, 16 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में दोपहर तीन बजे तक औसतन 72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अगरतला नगर निगम (एएमसी) के कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा।

उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों और लोगों की ओर से शिकायतें मिली हैं, जिनमें मतदान के दिन धमकी देने, हमला करने और डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। चक्रवर्ती ने कहा, ''हम कानूनी कार्रवाई के लिए इन शिकायतों की जांच कर रहे हैं।

10 राजमार्गों पर होगा हाइड्रोजन वाहनों का परीक्षण: गडकरी

नागपुर,एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एक ऐलान में कहा कि आयातित पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की कोशिशों के तहत देश भर के 10 राजमार्गों पर हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।यहां 'एग्रोविजन' कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि चुनिंदा राजमार्गों पर हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रैक्टर, बसें और अन्य वाहनों के लिए टाटा और महिंद्रा सहित प्रमुख वाहन निर्माताओं के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद हाइड्रोजन को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में स्थापित करना है।

भाजपा तेलंगाना को कांग्रेस-मुक्त बनाएगी: राव

हैदराबाद, एजेंसी।



तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य को कांग्रेस से मुक्त करेगी।राव ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में श्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए उन पर 'दिमागी दिवालियापन' का आरोप लगाया और कहा कि वे राज्य में भाजपा की चुनावी जीतों को भूल गए हैं।राव ने सोशल मीडिया पर नागरकुर्नूल जिले के अचंपेट में एक जनसभा के दौरान श्री रेवंत रेड्डी की उस टिप्पणी का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना में भाजपा की मौजूदगी पर सवाल उठाया था।

राव ने कहा कि मुख्यमंत्री कामारेड्डी, मलकाजगिरी और महबूबनगर में भाजपा की जीतों को भूल गए हैं।उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने कामारेड्डी विधानसभा क्षेत्र में श्री रेवंत रेड्डी को हराया था, जहां वे तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके अलावा भाजपा ने मलकाजगिरी लोकसभा सीट भी जीती, जिसका प्रतिनिधित्व पहले श्री रेवंत रेड्डी करते थे। भाजपा ने महबूबनगर लोकसभा क्षेत्र भी जीता, जिसके अंतर्गत रेवंत रेड्डी का विधानसभा क्षेत्र आता है।

नवीन के खिलाफ मुख्यमंत्री की टिप्पणी की निंदा करते हुए श्री राव ने कहा कि भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता भी अपनी योग्यता के दम पर संगठन के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है।

कांग्रेस अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी : इमरान मसूद

लखनऊ, एजेंसी।



कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ सीट के बंटवारे का समझौता तभी स्वीकार करेगी, जब वह सम्मानजनक और दोनों पक्षों को मंजूर हो।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मसूद ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है और उसी के अनुरूप अपनी मांगें रख रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस आगामी चुनाव में 105 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा, हम 2017 में पहले ही 107 सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। गठबंधन का समझौता सम्मानजनक और स्वीकार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर गठबंधन नहीं होना चाहिए। हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे।

उनका भी अपना सम्मान है और हमारा भी। यह हमारे स्वाभिमान की कीमत पर नहीं हो सकता। मसूद ने स्पष्ट किया कि वह गठबंधन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उन शर्तों पर आपत्ति जता रहे हैं, जिनके आधार पर दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है।

जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस विधायक सैयद का निधन

श्रीनगर,एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक पीरज़ादा मोहम्मद सैयद का निधन हो गया है।वह 73 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे।जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति (जेकेपीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष श्री सैयद चार बार मंत्री रहे और 2024 हुए विधानसभा चुनाव में अनंतनाग सीट से जीत हासिल की। उनका राजनीतिक करियर लगभग पांच दशकों तक चला और अपने लंबे राजनीतिक जीवन में वह विभिन्न सरकारों में मंत्री भी रहे।

वह 2003 से 2008 तक जेकेपीसीसी अध्यक्ष रहे और 1977 से 1986 तक जम्मू-कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पहले जेके यूथ कांग्रेस के महासचिव के तौर पर काम किया।

परिसीमन भाजपा की सबसे बड़ी गलती होगी : अखिलेश

लखनऊ, एजेंसी।



समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रस्तावित परिसीमन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ''सबसे बड़ी भूल'' साबित होगी और दावा किया कि इस कवायद का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को प्रभावित करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में परिसीमन से जुड़े नये महिला आरक्षण विधेयक को संभवतः मंजूरी दे दी गई और इसे अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में इस विधेयक को मंजूरी के लिए पेश किया गया। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल ने कुछ संशोधनों के साथ इसे मंजूरी दे दी। इन संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में किसी भी राज्य की हिस्सेदारी अन्य राज्यों की तुलना में कम न हो।

यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, परिसीमन भाजपा की सबसे बड़ी भूल होगी।

उन्होंने आरोप लगाया, जब उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव उनके हाथ से निकल रहे हैं, और चंदा चोरी तथा श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी के विवाद के बाद, उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने और पूरे देश को गुमराह करने के लिए परिसीमन लाने की शुरुआत कर दी। यादव ने कहा कि नोटबंदी सहित भाजपा सरकार द्वारा लिए गए कई बड़े फैसले अपेक्षित लाभ नहीं दे पाए। उन्होंने 2016 की नोटबंदी के दौरान जन्मे एक बच्चे का जिक्र करते हुए कहा, आज भी हम खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान हुआ था। यादव ने कहा, सरकार ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप और हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितने गुना बढ़ गया है।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के केंद्र के दावों में कोई सच्चाई नहीं है।

यादव ने कहा, हमें भरोसा दिलाया गया था कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आज भी हम सुनते हैं कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है।

उन्होंने यह भी सवाल किया कि सरकार ने वर्ष 2014 से पहले भारत के क्षेत्रीय दायरे और मौजूदा स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए पूछा कि 2014 के बाद से साबुन, बिस्कुट, खाद्य तेल, रसोई गैस, चीनी और बिजली जैसी रोजमर्रा की चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। यादव ने भाजपा के 'एक देश, एक चुनाव' प्रस्ताव पर भी तंज कसते हुए कहा, जो लोग 'एक देश, एक चुनाव' की बात करते हैं, वे एक मतदाता सूची तक तो सुनिश्चित कर नहीं पा रहे हैं।

सार समाचार

सुधा यादव की उद्योगों से बेंगलुरु के बाहर भी निवेश की अपील

बेंगलुरु,एजेंसी। कर्नाटक की राज्यपाल डॉ. सुधा यादव ने शुक्रवार को उद्योगों और कॉरपोरेट संगठनों से बेंगलुरु से आगे बढ़कर ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में भी अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भारी असमानता पर चिंता जताई। डॉ. यादव ने बताया कि कर्नाटक के दूर-दराज के इलाकों में अभी भी कई महत्वपूर्ण विकास कार्य अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति को केवल औद्योगिक विकास और शहरी समृद्धि के आधार पर नहीं मापा जा सकता।

लोकसभा में 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी के रुख पर द्रमुक अडिग

नई दिल्ली, एजेंसी।



संसद का विशेष सत्र बुलाये जाने और परिसीमन को लेकर बढ़ी सरगर्मी के बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि किसी भी परिस्थिति में लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18 प्रतिशत सीटों की हिस्सेदारी को कम नहीं किया जाना चाहिए।

द्रमुक प्रमुख ने कहा कि राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात 1971 की जनगणना पर आधारित है और इसे इसी आधार पर बनाए रखने की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने मांग की कि अगले 25 वर्षों तक भी इसी आधार पर लोकसभा की सीटों का परिसीमन होना चाहिए।

स्टालिन ने एक बयान में कहा कि द्रमुक लोकसभा सीटों में तमिलनाडु की 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व के अनुपात की अपनी मांगों पर अडिग है। केंद्र की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा परिसीमन के मुद्दे पर आगे बढ़ने की संभावनाओं के बीच द्रमुक अध्यक्ष ने कहा, हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और न ही इस पर कोई समझौता हो सकता है। द्रमुक तमिलनाडु के हितों से कभी समझौता नहीं करेगी और न ही अपने सिद्धांतों से हटेगी।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद द्रमुक का साथ छोड़ सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के साथ जाने वाली कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्टालिन ने कहा, सत्ता और पदों के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग देने वाले बेशर्म और कृतघ्न लोगों को यह बात समझ लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न तो मीडिया में चल रही अटकलें और न ही पीठ में छुरा घोंपने वालों का रोना-धोना द्रमुक के संकल्प को डिगा सकता है। द्रमुक प्रमुख ने याद दिलाया कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव और निष्पक्ष परिसीमन के लिए संयुक्त कार्य समिति की बैठक (22 मार्च 2025) में अपनाए गए प्रस्तावों के अनुरूप, उनकी पार्टी ने दो स्पष्ट मांगें रखी थीं।

स्टालिन ने मांगों का उल्लेख करते हुए कहा, अगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो किसी भी स्थिति में लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18 प्रतिशत सीट हिस्सेदारी में कटौती नहीं होनी चाहिए। यह अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया गया और पहले से ही स्थिर किया गया था तथा मौजूदा अनुपात को अगले 25 वर्षों तक और स्थिर रखना चाहिए।

मंत्रिमंडल में महिला और पिछड़े वर्ग को मिले प्रतिनिधित्व: सिद्दारमैया

बेंगलुरु,एजेंसी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को उम्मीद जताते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के दो रिक्त मंत्री पदों में से एक पद किसी महिला को और दूसरा पिछड़े वर्ग के किसी नेता को आवंटित होना चाहिए।यहां विधायक भवन में कनक जयंती के अवसर पर समाज सुधारक कनकदास को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में इन दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर सिद्दारमैया ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

परिसीमन का समर्थन करने का फैसला किया गया है : आव्हाड

मुंबई, एजेंसी।



राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा-शरदचंद्र पवार) के नेता जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने परिसीमन का समर्थन करने का फैसला किया है। हालांकि, पार्टी के लोकसभा में मुख्य सचेतक और शिरूर से सांसद अमोल कोल्हे ने कहा कि विधेयक का अध्ययन करने के बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।

पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवक्ता आव्हाड ने कहा, ''शरद पवार का फैसला मेरे और बाकी सभी लोगों के लिए अंतिम है। 'साहेब' (पवार) ने कहा है कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे देर-सवेर होना ही है। इसका समर्थन करने का फैसला किया गया है। हमारे सांसद विधेयक का गहन अध्ययन करेंगे और (कार्यकारी अध्यक्ष) सुप्रिया सुले द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि, जब इस बारे में कोल्हे से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने आव्हाड के बयान का समर्थन नहीं किया। कोल्हे ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में पार्टी के आठों लोकसभा सदस्यों को उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है।

राज्यपाल ने सेना की भूमिका बढ़ाने पर दिया जोर

ईटानगर,एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) केटी परनाइक ने गुरुवार को सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में सशस्त्र बलों की भूमिका का विस्तार करने और भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण को एक व्यवस्थित रूप देने का आह्वान किया है, ताकि अरुणाचल के अधिक से अधिक युवा सेना में शामिल हो सकें।परनाइक ने राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा प्रमुख (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि के साथ हुई एक बैठक के दौरान ये सुझाव दिए।

उन्होंने बैठक में सीमा सुरक्षा, रणनीतिक बुनियादी ढांचे, जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वीवीपी) और स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव बढ़ाने वाली पहलों पर चर्चा की।

शबरिमला में भीड़ कम होने की बात को टीडीबी प्रमुख ने नकारा

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी।

त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के अध्यक्ष के. जयकुमार ने शुक्रवार को शबरिमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में मौजूदा तीर्थयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के दावों को खारिज किया। टीडीबी अध्यक्ष ने कहा कि अतिरिक्त स्पॉट बुकिंग केंद्र खोलने का फैसला केरल उच्च न्यायालय से विचार-विमर्श और उसकी मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि करीब 80,000 श्रद्धालुओं ने पहाड़ी मंदिर में दर्शन किए। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा तीर्थयात्रा सीजन के शुरुआती दो-तीन दिनों में अपेक्षाकृत कम श्रद्धालुओं के आने के बाद अब उनकी संख्या सामान्य हो गई है।

जयकुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, ''अधिक स्पॉट बुकिंग केंद्र खोलने की मांग आई है, लेकिन हम इस पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकते। इस मामले की जानकारी अदालत को देनी होगी और उसकी अनुमति लेनी होगी।''

उन्होंने कहा कि बोर्ड को फिलहाल बुकिंग स्लॉट कृत्रिम तरीके से रोकने या बड़े पैमाने पर बुकिंग रद्द किए जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। ऐसी समस्याओं के कारण तीर्थयात्रा सीजन के शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं को कथित तौर पर परेशानी हुई थी।उन्होंने कहा कि अब श्रद्धालु लॉग इन करते ही स्लॉट प्राप्त कर सकते हैं और पर्याप्त स्पॉट बुकिंग सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि जब महिलाएं तरक्की करती हैं, तो समाज को भी लाभ होता है

न्यायपूर्ण समाज के बिना स्वस्थ समाज नहीं हो सकता: न्यायमूर्ति मनमोहन

नई दिल्ली, एजेंसी।



उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने शुक्रवार को कहा कि किसी समाज को तब तक स्वस्थ नहीं माना जा सकता जब तक कि वह न्यायपूर्ण न हो तथा उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की प्रतिदिन की अनदेखी को खत्म करने की अपील की।

'सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्यान' में मुख्य अतिथि के तौर पर, शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना ही नहीं है।

न्यायमूर्ति भंडारे, जिन्हें 1984 में दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था और जिनका 1994 में निधन हो गया, उन्हें महिलाओं के अधिकारों के समर्थक के रूप में याद किया जाता है। 'न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे फाउंडेशन' हर साल उनके सम्मान में एक स्मृति व्याख्यान आयोजित करता है।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने सवाल किया, कोई अस्पताल किसी खास बीमारी से पीड़ित मरीज का इलाज तो कर सकता है, लेकिन क्या वह ऐसे समाज का इलाज कर सकता है जो अपनी 'आधी आबादी' के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता या उसे पूरे अधिकार नहीं देता?

न्यायाधीश ने बताया कि वह दिवंगत न्यायमूर्ति भंडारे को बचपन से जानते थे, क्योंकि उनके माता-पिता और न्यायमूर्ति भंडारे के परिवार के बीच मैत्री संबंध थे। उन्होंने उन्हें एक निडर और साहसी न्यायाधीश के रूप में याद किया, जो अक्सर अपने बेहतरीन व्यावहारिक के आधार पर फैसले लेती थीं। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत इस सवाल से की कि परिवार में आमतौर पर कौन सबसे आखिर में खाना खाता है, अंत में आराम करता है और डॉक्टर के पास जाता है। उन्होंने कहा, आमतौर पर यह घर की महिला होती है... हमें यही सिखाया गया है कि इसे सामान्य माना जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम जिसे सामान्य मानते हैं, उस पर सवाल उठाएं।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि जब महिलाएं तरक्की करती हैं, तो समाज को भी लाभ होता है।

उन्होंने कहा कि एक शिक्षित महिला अधिक स्वस्थ होगी, ज्यादा कमाएगी और परिवार के लिए सोच-समझकर फैसले ले सकेगी।

उन्होंने कहा कि बदलाव की शुरुआत घर से होनी चाहिए, जहां लड़कियों को शिक्षित किया जाए और उन्हें अच्छा पोषण दिया जाए। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसे सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों, पुलिस और पूरे समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, हम खुद को तभी एक स्वस्थ समाज कह सकते हैं, जब हम एक न्यायपूर्ण समाज हों।

न्याय के बिना, एक स्वस्थ समाज नहीं बन पाएगा। न्यायाधीश ने माना कि भारत ने काफी प्रगति की है; उन्होंने मातृ मृत्यु दर में कमी (प्रति एक लाख जन्म पर लगभग 97) और चिकित्साकर्मी की देखरेख में होने वाले प्रसव में वृद्धि (लगभग 88.6 प्रतिशत) का हवाला दिया।

कांग्रेस के 55 साल पर भारी पड़े ढाई साल: डॉ. यादव

प्रदेश में सिंचाई रकबा 60 लाख हेक्टेयर पहुंचने का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दावा

सीहोर, एजेंसी।



मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। उन्होंने कांग्रेस के 55 वर्ष के शासनकाल की तुलना अपनी सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल से करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सीहोर जिले के भैरूंदा में 536.23 करोड़ रुपये की सीप-अंबर माइक्रो सिंचाई परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण का लोकार्पण किया।

इस परियोजना से भैरूंदा विकासखंड के 76 गांवों की 30,091 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने 41.44 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया।मुख्यमंत्री के भैरूंदा पहुंचने पर हेलीपेड पर विधायक सुदेश राय ने उनकी अगवानी की। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर सीप-अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के दोनों चरणों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और संबोधित किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिला प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रमाकांत भार्गव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मां नर्मदा अब किसानों के गांवों और खेतों तक पहुंच रही हैं। वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और खेती की चुनौतियों को समझते हैं। सूखे खेत में पानी पहुंचते ही फसल सोने जैसी हो जाती है। सरकार का संकल्प किसानों की जिंदगी बदलना और उनकी आय में लगातार वृद्धि करना है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 55 साल के शासनकाल में प्रदेश का सिंचाई रकबा महज साढ़े सात लाख हेक्टेयर तक पहुंच पाया था। इसके बाद उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में यह बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हुआ। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने ढाई साल में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया है।

उन्होंने बिजली व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि अब किसानों को दिन में भी बिजली मिल रही है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में रात में भी बिजली मिलना मुश्किल था।सीप-अंबर माइक्रो सिंचाई परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण 346.12 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसके तहत 16.57 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे 47 गांवों की 15,284 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस चरण का निर्माण रीवा की मेसर्स विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है।

परियोजना के द्वितीय चरण पर 190.11 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके तहत 24.09 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे 29 गांवों की 14,807 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। इस चरण का निर्माण अहमदाबाद की एलसीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। दोनों चरणों पर कुल 536.23 करोड़ रुपये की लागत आई है और इनके माध्यम से 76 गांवों की 30,091 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भैरूंदा विकासखंड के लिए 41.44 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण और भूमिपूजन किया। परियोजना से किसानों को मिलने वाली सिंचाई सुविधा का लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि पानी निर्धारित गांवों और खेतों तक कितनी तेजी से पहुंचता है।

जातिगत जनगणना के आंकड़ों के बिना परिसीमन स्वीकार नहीं : दीपक बैज

रायपुर, एजेंसी।



छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनगणना के आंकड़ों और जातिगत जनगणना को आधार बनाए बिना परिसीमन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैज ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि 30 नवंबर से तीन दिसंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाना लोकतांत्रिक एवं संसदीय परंपराओं के विपरीत है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार नियमित शीतकालीन सत्र से बचते हुए विपक्ष को विश्वास में लिए बिना संविधान संशोधन की तैयारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्ष 2029 के चुनावों से महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में है। सरकार को लोकसभा की वर्तमान सीटों पर ही बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण लागू करना चाहिए।

बैज ने कहा कि वर्ष 2011 के बाद से दशकीय जनगणना लंबित रहने और नई जनगणना के आंकड़े सामने आए बिना परिसीमन की जल्दबाजी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत जनगणना को परिसीमन का आधार नहीं बनाना अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिकारों और उचित प्रतिनिधित्व की अनदेखी करने की रणनीति है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा 'ऑपरेशन लोटस' और दलबदल के जरिए जुटाए गए कथित दो-तिहाई बहुमत के आधार पर संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि सभी राज्यों में आनुपातिक रूप से होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व को नुकसान न हो और अगले 25 वर्षों तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए।

बैज ने कहा कि परिसीमन से जुड़े किसी भी निर्णय में संघीय ढांचे, क्षेत्रीय हितों और सामाजिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाना चाहिए। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं, संसदीय संवाद और पारदर्शी प्रक्रियाओं को महत्व देती रही है।

सार समाचार

पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी का मॉड्यूल पकड़ा

नकोदर,एजेंसी। पंजाब में जालंधर ग्रामीण पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश कर 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 12 किलो हेरोइन, चार पिस्तौल, पांच कारतूस, दो मैगजीन, आईफोन और आईपैड बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी की महिंद्रा बोलेरो भी जब्त की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांव आवां चुहर्मी निवासी प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ के रूप में हुई है। उसके कथित खुलासे के आधार पर पुलिस ने अमेरिका में रह रहे नवजोत सिंह उर्फ गैरी को भी मामले में नामजद किया है।

केजरीवाल ने पंजाब को लूटना शुरू किया: सांपला

जालंधर,एजेंसी। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सरकारी आवास पर भारी धनराशि खर्च की और अब पंजाब में भी इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के पूर्व मुख्यमंत्री आवास को आम लोगों के लिए खोले जाने के बाद सामने आई तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांपला ने कहा कि सत्ता में आने से पहले केजरीवाल सरकारी बंगला नहीं लेने, वैगनआर कार में चलने और वीआईपी संस्कृति खत्म करने की बातें करते थे, लेकिन उनके आवास की तस्वीरें उनके दावों की पोल खोलती हैं। सांपला ने कहा कि आवास के बाहर लगे बोर्ड के अनुसार, परियोजना का शुरुआती बजट आठ करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 58.83 करोड़ रुपये हो गया।

वांगचुक ने शांति बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार

श्रीनगर, एजेंसी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में लेह में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए। उन्होंने अनौपचारिक रूप से स्पष्ट किया कि शांति बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का बॉन्ड, यहां तक कि अंतरिम शांति बॉन्ड भी हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा या किया नहीं है जिससे शांति भंग होने की आशंका हो।

लेह प्रशासन ने वांगचुक को कल तलब किया था और उनसे पूछा था कि आगामी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनावों के मद्देनजर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें बांड भरने के लिए बाध्य क्यों न किया जाए।वांगचुक ने बताया कि उन्हें चुनाव अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए बांड भरने के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए तलब किया गया था।

परिसीमन से बढ़ेगा जनप्रतिनिधित्व, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी होगी मजबूत: साय

रायपुर, एजेंसी।



छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि परिसीमन से लोकसभा और विधानसभाओं में जनप्रतिनिधित्व का विस्तार होगा तथा महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे।साय ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान संसद के विशेष सत्र, परिसीमन, महिला आरक्षण और कांग्रेस नेताओं के आरोपों से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि यदि संसद में परिसीमन विधेयक लाया जाता है, तो यह स्वागतयोग्य पहल होगी।

लोकतांत्रिक संस्थाओं में व्यापक जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम देश के लिए लाभकारी होंगे।उन्होंने कहा कि परिसीमन से विभिन्न क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तथा उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलेगा। इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इसके साथ ही नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति समाज के सभी वर्गों की सहभागिता में निहित है।

संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए साय ने कहा कि लगातार चुनावी पराजय के कारण कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता का विश्वास खोने के बाद कांग्रेस नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम पक्ष में आने पर कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), निर्वाचन आयोग और पूरी चुनावी व्यवस्था पर भरोसा रहता है, लेकिन हार मिलने पर वह इन्हीं संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है।

साय ने कहा कि कांग्रेस को अपनी लगातार हो रही चुनावी पराजय के कारणों पर आत्ममंथन करना चाहिए। जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने के बजाय कांग्रेस नेता अपनी विफलताओं का दोष लोकतांत्रिक संस्थाओं पर मढ़ रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की स्थिति को 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' जैसी बताते हुए कहा कि चुनाव जीतने पर सब कुछ सही और हारने पर हर व्यवस्था में खामी निकालना कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के इस रवैये को अच्छी तरह समझ चुकी है।

उत्तर प्रदेश में 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

लखनऊ,एजेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 28 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसके तहत नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज के पुलिस आयुक्तों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह की तैनाती आपस में बदल दी गई है।

लक्ष्मी सिंह पिछले चार वर्षों से गौतमबुद्धनगर की पुलिस आयुक्त थीं। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत उनका तबादला गाजियाबाद किया गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना बनाया गया है, जबकि वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।

भोपाल-कानपुर कॉरिडोर का 39.57 किमी हिस्सा फोरलेन तैयार



भोपाल,एजेंसी।

भोपाल-कानपुर कॉरिडोर पर मोहारी से सतई घाट के बीच 39.57 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन में विकसित कर लिया गया है। करीब 710 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस मार्ग के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले पहाड़ी और घाटी वाले इस रास्ते को पार करने में डेढ़ से दो घंटे लगते थे, जबकि अब यह सफर करीब 40 मिनट में पूरा होने का अनुमान है। इससे वाहन चालकों के लगभग 80 मिनट बचेंगे।

बुंदेलखंड के इस मार्ग पर पहले संकरी सड़क, तीखे मोड़ और एस-बेंड होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। पहाड़ी ढलानों के कारण सामने से आने वाले वाहन भी देर से दिखाई देते थे। भारी वाहनों को निकलने में कठिनाई होती थी और कई बार जाम की स्थिति बन जाती थी। फोरलेन निर्माण के दौरान सड़क का अलाइनमेंट सुधारा गया तथा पहाड़ियों की कटिंग और घाटी वाले हिस्सों में भराव कर मार्ग को चौड़ा और सुगम बनाया गया है।

मोहारी-सतई घाट मार्ग सागर-छतरपुर-कबरई सड़क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तैयार होने से मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का उत्तरप्रदेश के महोबा, बांदा और कानपुर से सड़क संपर्क बेहतर होगा। इससे यात्रियों के साथ मालवाहक वाहनों को भी लाभ मिलेगा।

कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग किया : नितिन

पटना, एजेंसी।



भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर संविधान का सत्ता के लिए दुरुपयोग करने और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान को सत्ता का हथियार बनाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इसे गरीबों, पिछड़ों, वंचितों और महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बनाया है। नवीन ने कहा कि संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतिबिंब है।

भाजपा अध्यक्ष ने पटना में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित 'संविधान गौरव दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती का संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के विकास में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, बोधगया में भगवान बुद्ध की संघ परंपरा और पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासन से लोकतांत्रिक विमर्श, सहमति और लोककल्याण की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र सीखने के लिए दुनिया की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा दी है।

भाजपा नेता श्री नवीन ने संविधान के स्वरूप, आत्मा और प्राण की चर्चा करते हुए कहा कि संविधान का स्वरूप उसके अनुच्छेदों में, आत्मा भारत की सभ्यता और संस्कृति में तथा प्राण उन लोगों में निहित हैं, जो इसे लागू करते हैं और इसका पालन करते हैं।

सिरपुर महोत्सव 20 फरवरी से

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक नगरी सिरपुर में 20 से 22 फरवरी 2027 तक तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 'संगीति' की अवधारणा पर आधारित इस महोत्सव में इतिहास, अध्यात्म, कला, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी विविध गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। महोत्सव की तैयारियों को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में अंतरविभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धम्मशील गणवीर ने आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। महोत्सव का प्रमुख आकर्षण ऐतिहासिक सुरंग टीला में शुरू होने वाला प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम होगा। इसके माध्यम से सिरपुर के गौरवशाली इतिहास, पुरातात्त्विक विरासत और चीनी यात्री ह्वेनसांग की सिरपुर यात्रा से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा।

शिक्षा के जरिये ही विश्व गुरु बनेगा भारत: रामदेव

हरिद्वार, एजेंसी।



योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व गुरु बनना होगा। देश का भविष्य कैसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करती है, यह उसी पर निर्भर करता है कि आने वाली पीढ़ी का निर्माण किस रूप में होगा। शिक्षा में समग्रता, समानता और दक्षता का समावेश जरूरी है। उन्होंने सपना व्यक्त किया कि देश में ऐसा समय आए, जब 90 से 99 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने पर गौरव महसूस करें।

स्वामी रामदेव शुक्रवार को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभागार में काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (कोब्से) के तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 25 से 27 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में नेपाल और भूटान सहित देश के विभिन्न राज्यों के 41 स्कूली शिक्षा बोर्डों के करीब 91 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

सम्मेलन में बच्चों के सामाजिक-भावनात्मक विकास, कल्याण, शिक्षा की बदलती जरूरतों और उनके सर्वांगीण विकास से जुड़ी चुनौतियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान कोब्से की जनरल बॉडी की बैठक में 56वां सम्मेलन त्रिपुरा में आयोजित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।स्वामी रामदेव ने कहा कि देश का निर्माण केवल नारों से नहीं, बल्कि शिक्षा के माध्यम से होगा। योग और आयुर्वेद भी शिक्षा के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

शिक्षा में दृष्टि और दक्षता दोनों का समावेश होना चाहिए। बच्चों को प्रत्येक विषय समग्रता के साथ समझाना और उनके चित्त एवं मानस का निर्माण करना शिक्षकों व शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जीवन में विकल्प रहित संकल्प जरूरी है। बच्चों में उत्साह बनाए रखते हुए उन्हें छोटे उद्देश्यों तक सीमित रखने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।कोब्से के महासचिव एमसी शर्मा ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि तीन दिनों में विभिन्न विषयों पर कुल 12 प्रस्तुतिकरण किए गए। नेपाल, भूटान और देश के विभिन्न राज्यों के 41 शिक्षा बोर्डों के करीब 91 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया।

उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि गंगा आरती से लेकर भारतीय शिक्षा बोर्ड की मेजबानी तक सभी व्यवस्थाएं शानदार रहीं। उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड को देशभर में अपनी पहुंच बढ़ाने और नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दीं।कोब्से के अध्यक्ष डॉ. जी. इम्मानुएल ने सम्मेलन को सफल बताते हुए कहा कि तीन दिनों के दौरान शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

उन्होंने भारतीय शिक्षा के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय शिक्षा बोर्ड (बीएसबी) भविष्य में देश का एक बेहतरीन शिक्षा बोर्ड बनेगा। साथ ही सम्मेलन में मार्गदर्शन और सहभागिता के लिए स्वामी रामदेव का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री सैनी ने शुभंकर का अनावरण किया। 30 खेलों में 18 हजार खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

हरियाणा में खेल महाकुंभ-2026 का शुभंकर जारी

चंडीगढ़,एजेंसी।



हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को 'खेल महाकुंभ हरियाणा-2026' के शुभंकर का अनावरण किया। हरियाणा के राजकीय पशु काले हिरण से प्रेरित यह शुभंकर खिलाड़ियों की चपलता, सतर्कता, संतुलन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। खेल महाकुंभ में 30 खेल विधाओं में करीब 18 हजार खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिताएं प्रदेश के 11 शहरों में दो चरणों में आयोजित की जाएंगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का जुनून और उत्साह राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। खेल महाकुंभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की उभरती प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के साथ अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार पर करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। राज्य में 2,000 खेल नर्सरियां संचालित हैं, जहां लगभग 40 हजार बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा 25 आवासीय खेल अकादमियां स्थापित की गई हैं। अब तक 260 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप ए, बी और सी में सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि 17,676 खिलाड़ियों को 931 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को छह करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। पंचकूला के ताऊ देवी लाल खेल परिसर में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 30 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वहीं एशियाई पैरा गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 31 पदक हासिल किए। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की।

खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से अंतरराष्ट्रीय पदक तक पहुंचाना है। मिशन ओलंपिक-2036 के तहत हरियाणा ने 36 पदक जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि इस बार खेल महाकुंभ का बजट पिछले संस्करण के मुकाबले दोगुना किया गया है।

इस अवसर पर खेल विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह, एशियाई खेल पदक विजेता परवीन हुड्डा और मुक्केबाज नरेंद्र सहित कई अधिकारी एवं खिलाड़ी मौजूद रहे।

रोजगार मेले में 294 युवाओं का प्रारंभिक चयन

निवाड़ी, एजेंसी।

युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और निजी क्षेत्र की कंपनियों से जोड़ने के उद्देश्य से शुक्रवार को शासकीय पीजी कॉलेज निवाड़ी में युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया।

कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में आयोजित मेले में 11 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में शामिल 380 आवेदकों में से 294 का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन किया गया, जबकि 121 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। इसके अलावा 14 आवेदकों का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ।

मेले में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं के साक्षात्कार लेकर उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की। इसमें वर्धमान फैब्रिक्स बुधनी, सागर मैन्युफैक्चरर्स भोपाल, एसआईएस सिक्योरिटी अनूपपुर, ग्रेट ऑर्गेनिक डायमंड सागर, ग्रोफास्ट एग्रीटेक सागर, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन झांसी, चेकमेट सर्विसेज वडोदरा, नौकरी फाय डॉट कॉम भिंड, वीई कमर्शियल व्हीकल्स (आयशर) भोपाल, ईस्टर्न रिफ्रैक्टरीज निवाड़ी और भारतीय जीवन बीमा निगम निवाड़ी शामिल रहे।

रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी के साथ स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप की संभावनाओं की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, उपलब्ध सहायता और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लाभों से युवाओं को अवगत कराया।

लैथम और ब्लंडन के अर्धशतक, न्यूजीलैंड ने बनाये पांच विकेट पर 246

स्टंप के समय ग्लेन फिलिप्स (नाबाद 36) और ब्लंडन (नाबाद 53) क्रीज पर मौजूद थे।

क्राइस्टचर्च, एजेंसी। कप्तान टॉम लैथम और टॉम ब्लंडन (नाबाद 59) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड शुक्रवार को हेगले ओवल में दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 246 रन बना लिये है। चायकाल के बाद न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल और टॉम ब्लंडन की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का जमकर सामना किया। 65वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने डैरिल मिचेल को आउटकर भारत को पांचवी सफलता दिलाई।



इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ग्लेन फिलिप्स ने ब्लंडन के साथ पारी को संभाला और रन भी बटोरे। स्टंप के समय ग्लेन फिलिप्स (नाबाद 36) और ब्लंडन (नाबाद 53) क्रीज पर मौजूद थे1 भारत की ओर आकाश दीप ने दो विकेट लिये। अंशुल कम्बोज, वॉशिंगटन सुंदर और गुरनूर बरार ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने भोजकाल तक न्यूजीलैंड का स्कोर एक विकेट पर 77 रन कर दिया था।

इस दौरान कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने 77 रन की ओपनिंग साझेदारी की। हालांकि, ब्रेक के बाद भारतीय तेजबाजी गेंदबाजों ने वापसी की, और एक के बाद एक तीन अच्छी तरह से सेट बल्लेबाजो को आउट करके मैच का रुख पलट दिया। लैथम ने 128 गेंदों पर छह बाउंड्री लगाकर 59 रन बनाए, जबकि कॉनवे ने 79 गेंदों पर 31 रन बनाए। हेनरी निकोल्स ने अंशुल कंबोज का शिकार होने से पहले 16 रन बनाए। लैथम ने छह चौकों की मदद से अपना 32वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूज़ीलैंड 36 ओवर में 100 रन पर पहुँच गया। वह अपनी पारी के दौरान आराम से खेल रहे थे लेकिन आखिर में आकाश दीप ने उन्हें आउट कर दिया।

आकाश ने एक शानदार गेंद डाली जो लैथम की तरफ़ झुकी और फिर ऑफ़-स्टंप के बाहर अपनी लाइन पर आ गई। न्यूज़ीलैंड के कप्तान ने गेंद को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में दे दिया, जिससे उनका स्कोर दो विकेट पर 110 रन हो गया। भारत को अगले ओवर में फिर झटका लगा जब कंबोज ने निकोल्स को आउट किया। बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने एक छोटी गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन शॉट लगाने में चूक गए।

जिससे गेंद का टॉप एज लॉन्ग लेग की तरफ़ चला गया, जहाँ आकाश दीप ने कैच पूरा किया। निकोल्स 46 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आकाश ने उसी ओवर में रचिन रवींद्र को बिना खाता खोले आउट किया, जिससे एक और गेंद पिच होने के बाद बाहर चली गई। रवींद्र ने धीरे से गेंद को मारा और गेंद स्टंप के पीछे पंत के पास पहुँच गई। इस दोहरे झटके से न्यूज़ीलैंड का स्कोर दो विकेट पर 110 से घटकर चार विकेट पर 110 हो गया, जिससे भारत को एक अहम ब्रेकथ्रू मिला, जबकि मेज़बान टीम अच्छी स्थिति में दिख रही थी।

इससे पहले, लैथम और कॉनवे ने भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ़ पहले सत्र में धैर्य से काम लिया। कॉनवे ने चार बाउंड्री लगाईं, जबकि लैथम ने तीन बार बाउंड्री पार की। दोनों ने 19वें ओवर में अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। भारत के पास लैथम को आउट करने का शुरुआती मोका था जब 15वें ओवर में आकाश दीप की गेंद पर केएल राहुल ने दूसरी स्लिप में उनका कैच छोड़ दिया। लैथम पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पगबाधा अपील से भी बच गए, जब उन्होंने फैसले का सफलतापूर्वक रिव्यू किया, बॉल-ट्रैकिंग से पता चला कि डिलीवरी लेग-स्टंप के थोड़ा बाहर पिच हुई थी।

स्पेन ने कटाया डेविस कप के सेमीफाइनल का टिकट

बोलोग्ना,एजेंसी। स्पेन ने गुरुवार को ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर डेविस कप फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम की जीत की नींव डेनियल मेरिडा ने रखी, जिन्होंने पहला मुकाबला जीतकर स्पेन को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद राफेल जॉडार ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछड़ने के बावजूद वापसी की और अपना मैच जीतकर स्पेन की टाई में जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत के साथ स्पेन ने कुल मिलाकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की और सेमीफाइनल का टिकट कटाया।



एटीपी फाइनल्स में अपनी सफलता के बाद मौजूद रहे कार्लोस अल्काराज को कोर्ट पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्पेन का शनिवार को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ आखिरी-चार का मुकाबला होना था। मेरिडा ने शुरुआती सिंगल्स मुकाबले में जोएल श्वार्जलर पर 6-4, 6-4 की शांत जीत के साथ स्पेन की जीत की नींव रखी। फिर जॉडार ने यह पक्का किया कि निर्णायक डबल्स मैच की जरूरत न पड़े, और जुरिज रोडियोनोव के खिलाफ 2-6, 6-0, 6-1 से शानदार जीत हासिल की। पहला सेट हारने के बाद 20 साल के खिलाड़ी का जवाब खास तौर पर शानदार था, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए आखिरी 13 में से 12 गेम जीते। उनकी पहली सर्विस की काबिलियत अहम साबित हुई, जिसमें रोडियोनोव के साथ अपनी पहली एटीपी मीटिंग में जॉडार ने अपनी पहली डिलीवरी के बाद 94 प्रतिशत (63/67) पॉइंट जीते।

जॉडार ने स्पेन के कप्तान डेविड फेरर को मुश्किल शुरुआती दौर के बाद खुद को संभालने में मदद करने का क्रेडिट दिया और माना कि पूर्व टेनिस स्टार के मार्गदर्शन से उन्हें बाकी मैच में ज्यादा आजादी से खेलने में मदद मिली। एटीपी ने जॉडार के हवाले से कहा, मुझे लगता है कि कप्तान डेविड (फेरर) की सलाह ने मुझे दूसरा सेट ज्यादा कॉन्फिडेंस और अधिक रिलैक्स होकर शुरू करने में सच में मदद की। मुझे यही करना था। मैं डेविस कप मैच में था, इसलिए मुझे एंजॉय करना था और खुलकर खेलने की कोशिश करनी थी। मैंने यही सबसे अच्छा किया।

सैंडपेपरगेट विवाद की फिर होगी जांच

नई दिल्ली,एजेंसी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने वरिष्ठ अधिवक्ता फियोना मैकलियोड एओ एससी को एक स्वतंत्र समीक्षा पैनल का प्रमुख नियुक्त किया है। यह पैनल ऑस्ट्रेलिया के 2018 के दक्षिण अफ्रीका टेस्ट दौरे के दौरान हुए विवादित घटनाक्रमों की जांच करेगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि समीक्षा की यह प्रक्रिया लगभग छह सप्ताह तक चलेगी। इसके बाद एक रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी, जिन्हें पूरी तरह सार्वजनिक किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सबसे बदनाम घटनाओं में से एक के 8 साल बाद उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब ₹सब्र₹ में दावा किया कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बॉल-टैम्परिंग की कोशिशों के बारे में पता था और तर्क दिया कि बैनक्रॉफ्ट, स्मिथ और डेविड वार्नर को अकेले सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। किताब के लॉन्च और इसके खुलासों ने सैंडपेपरगेट विवाद को फिर से हवा देने का काम किया।

मैकलियोड के पास रॉयल कमीशन सहित जटिल और संवेदनशील मामलों की जांच का तीन दशक से अधिक का अनुभव है। वह दक्षिण अफ्रीका दौरे और उसके बाद हुई जांच से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करने और उनसे जानकारी जुटाने की प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। यह स्वतंत्र फोरम 2018 के दौरे में शामिल सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के साथ-साथ उस समय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) में जिम्मेदार पदों पर रहे अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों को भी अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करेगा।

पंड्या के ट्रेड के कारण रोहित वापस मुम्बई की कप्तानी की होड़ में

मुंबई,एजेंसी। मुंबई इंडियंस के नए मुख्य कोच कीरोन पोलार्ड ने न केवल कप्तानी के सवाल पर अपनी बात रखी होगी - जहां रोहित शर्मा संभावित पसंद के रूप में उभरे हैं - बल्कि उस हाई-प्रोफाइल ट्रेड में भी, जिसने अर्शदीप सिंह के बदले हार्दिक पंड्या को पंजाब किंग्स में भेजा था।



क्रिकबज समझता है कि पोलार्ड से पिछले महीने मुंबई में उनके कुछ दिनों के दौरान कप्तानी की घोषणा से पहले सलाह ली गई थी, जो शुक्रवार को शाम 5.45 बजे होने की उम्मीद है। चाहे वह रोहित हों, सूर्यकुमार यादव हों, तिलक वर्मा हों या यहां तक कि मिशेल सैंटनर - हां, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी भी दावेदारी में था - मुख्य कोच के रूप में पोलार्ड के आने या यूं कहें कि घोषणा के बाद कप्तानी को लेकर सोच बदल गई है।

यहां तक कि जसप्रीत बुमराह के नाम पर भी संक्षेप में विचार किया गया। बाद में प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि तिलक के लिए बागडोर संभालना जल्दबाजी होगी, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट में रोहित और सूर्यकुमार को शामिल किया गया। इस बीच, सेंटनर को इस आधार पर बाहर कर दिया गया कि अंतर्निहित चुनौतियों के कारण आईपीएल टीम के लिए एक विदेशी कप्तान रखना आदर्श व्यवस्था नहीं है। यह रोहित और सूर्यकुमार को अंतिम दौड़ में छोड़ देता है, जिसमें पूर्व सबसे आगे हैं।

इस बीच, चतुराई से डिजाइन किए गए सोशल मीडिया पोस्ट की श्रृंखला की बदौलत एमआई ने घोषणा के इर्द-गिर्द काफी हलचल मचाने में कामयाबी हासिल की है।

कुछ सिद्धांतों ने शाम 5.45 बजे के खुलासे के महत्व को समझने का भी प्रयास किया हैः रोहित के तहत एमआई द्वारा जीते गए आईपीएल खिताबों की संख्या पांच और उनकी जर्सी संख्या 45 है। 27 तारीख को भी महत्व दिया जा रहा है, जिस दिन 2023 में पंड्या का मुंबई इंडियंस के साथ व्यापार स्पष्ट रूप से हुआ था।

वही तारीख अब आईपीएल की दो सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए निर्धारित है। ब्रांड मार्केटिंग और डिजिटल ग्रोथ के प्रमुख रोशन पॉल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक सीधे रोल-आउट को एक ऑल-आउट इवेंट में बदल दिया गया है।

इस विषय पर लगभग 12 मिलियन रीलें हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उच्च आकर्षण और जुड़ाव को दर्शाती हैं। पंड्या ट्रेड में भी पोलार्ड का हाथ साफ नजर आ रहा है. पहले सोच यह थी कि पंड्या के बदले एक बल्लेबाज और एक स्पिनर लाया जाए, और यशस्वी जयसवाल और रवि बिश्नोई का सौदा मुंबई इंडियंस को स्वीकार्य होता।

मैं अब बिना चिंता किए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगाः शमी

मुंबई,एजेंसी। तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी ने सफ़ेद गेंद प्रारूप में भारतीय टीम में वापसी के बारे में बहुत सोचना छोड़ दिया है। इसके बजाय वह अपनी घरेलू टीम बंगाल और आईपीएल में खेलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और उन्होंने कहा कि वह खेल का लुत्फ़ उठाने पर ध्यान दे रहे हैं।

शमी से जब मुंबई में यह पूछा गया कि क्या उनके ज़हन में 2027 का विश्व कप और 2028 का टी20 विश्व कप है तो उन्होंने कहा, ₹मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। वे (चयनकर्ता) जो भी निर्णय लेंगे बेहतर होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ़ से यही कर सकता हूं कि लय में बने रहूं और कम से कम राज्य के लिए और आईपीएल में खेलता रहूं।

शमी ने आख़िरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 खेला था और टेस्ट से संन्यास की घोषणा से पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी का पहला चरण भी खेला था। इसके बाद वह सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में भी खेले जिसमें उनकी टीम गुरुवार को मुंबई में टूर्नामेंट से बाहर हो गई। शमी ने सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में 43 की औसत से मात्र चार विकेट लिए थे जबकि रणजी ट्रॉफ़ी में उन्होंने इसकी तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीन मुक़ाबलों में 14 की औसत से 14 विकेट हासिल किए थे।

बिजनेस

एयर इंडिया का केएम माल्टा एयरलाइंस के साथ कोडशेयर समझौता

नई दिल्ली,एजेंसी। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने माल्टा की राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी केएम माल्टा एयरलाइंस के साथ साझेदारी का विस्तार करने की घोषणा की है। माल्टा यूरोप का एक द्वीपीय देश है जो अफ्रीका और यूरोपीय मुख्य भूमि के बीच स्थित है।

इस्पात की मांग नवंबर में 7.5 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली,एजेंसी। देश में इस्पात की मांग अक्टूबर में सालाना आधार पर 7.5 प्रतिशत बढ़कर 144 लाख टन पर पहुंच गई। इस्पात मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में कच्चे इस्पात का उत्पादन 3.6 प्रतिशत सालाना बढ़कर 145 लाख टन पर पहुंच गया।

दो-तीन दशकों तक दुनिया का पसंदीदा निवेश गंतव्य बना रहेगा भारतः गोयल

मुंबई,एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर के देशों के लिए भारत भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है और अगले दो-तीन दशकों तक दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बना रहेगा। गोयल ने यहां भारत ऋण पूंजी बाजार शिखर सम्मेलन 2026 में कहा कि तरजीही व्यापार समझौतों, द्विपक्षीय समझौतों और मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से दुनिया भर के देशों के साथ भारत की भरोसेमंद साझेदारी देश के जुड़ाव का प्रमुख आधार है।



भारत अब आगामी दो से तीन दशकों के लिए दुनिया के पसंदीदा साझेदार, आकर्षक निवेश गंतव्य और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में उभरकर सामने आया है। उन्होंने देश की बढ़ती विनिर्माण एवं निर्यात क्षमताओं, मुक्त व्यापार समझौतों के साथ बढ़ते एकीकरण और तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगले 30 वर्षों में भारत में जितनी नई इमारतों का निर्माण होने की उम्मीद है, उनकी संख्या देश में इस समय मौजूद सभी आवासीय और वाणिज्यिक इमारतों की कुल संख्या से भी अधिक होगी।

यह देश में बुनियादी ढांचे के विकास के व्यापक पैमाने और विभिन्न क्षेत्रों में उभरते अवसरों को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति और व्यापक आर्थिक आधार को देखते हुए तेल की कीमतों में कुछ डॉलर का उतार-चढ़ाव देश के दीर्घकालिक भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकता। उन्होंने उल्लेख किया कि देश का राष्ट्रीय ऋण स्तर दुनिया के सबसे कम ऋण स्तर वाले देशों में शामिल है और इसके कुल ऋण में बाहरी ऋण का हिस्सा भी काफी कम है।

ये सभी कारक देश की विकास गाथा की स्थिरता और दीर्घकालिक टिकाऊपन को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का आर्थिक परिवर्तन किसी संयोग या भाग्य का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले 12 वर्षों में लगातार किए गए सुधारों और विभिन्न क्षेत्रों में शुरू की गई परिवर्तनकारी पहलों का नतीजा है। सरकार का ध्यान नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, अच्छी सड़कें, गुणवत्तापूर्ण बिजली और डिजिटल संपर्क सुविधा शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि रही और दूसरी तिमाही में भी विकास गति कायम रहने की उम्मीद है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि चालू वर्ष के पहले सात महीनों में देश का निर्यात 570 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि भारत चालू वित्त वर्ष में एक ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार अगले 20 से 25 वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण देश की विकास व्यवस्था में मजबूती से समाहित है और भारत को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अगले दो दशकों में बिजली क्षेत्र में 200 लाख करोड़ के निवेश का अवसरः मनोहर लाल

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कहा कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में अगले दो दशकों के दौरान 200 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अवसर है। उन्होंने कहा कि इसे संभव बनाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। दो दिवसीय 'ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना होगा।



मनोहर लाल ने ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने और राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा, ₹हमारी यात्रा के अगले चरण में हमें ऊर्जा क्षेत्र की योजना बनाने के लिए एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

जहां बिजली उत्पादन, भंडारण, पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण को एक ही प्रणाली के परस्पर जुड़े हिस्सों के रूप में देखा जाए। उन्होंने बताया कि राज्यों के साथ सहयोग और विद्युत मंत्रालय की पहलों के कारण, लंबे समय के बाद डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। मनोहर लाल ने राज्यों और डिस्कॉम की सराहना की क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 में डिस्कॉम ने कुल मिलाकर सकारात्मक पीएटी (कर-पश्चात लाभ) दर्ज किया है।

उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे। साथ ही, नीति, संचालन और नियमों में ऐसे जरूरी बदलाव किए जाएं, जिससे यह सकारात्मक बदलाव आगे भी जारी रह सके। विद्युत राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने सम्मेलन में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने अनुभव साझा करने को कहा।

इसमें योजनाओं को लागू करने में आने वाली कठिनाइयां, नियामक मुद्दे और ऐसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां उन्हें केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग या हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। नाइक ने कहा, हमारा सामूहिक ध्यान नीति बनाने से आगे बढ़कर उसे प्रभावी ढंग से लागू करने, बुनियादी ढांचा तैयार करने से लेकर मापने योग्य परिणाम हासिल करने, और अलग-अलग प्रयासों के बजाय एक एकीकृत और टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र बनाने पर होना चाहिए।

भारतीय एमएसएमई एफटीए का पूरा लाभ नहीं उठा रहेः आरबीआई गवर्नर

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय निर्यातक, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), देश के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से मिलने वाले लाभों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भारत के केवल 20-30 प्रतिशत पात्र निर्यात ही टैरिफ रियायतों का लाभ उठा रहे हैं, वहीं भारत को निर्यात करने वाले साझेदार देशों द्वारा इन समझौतों का उपयोग 60-70 प्रतिशत तक किया जा रहा है।



मुंबई में आयोजित एसएमई फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट समिट को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि भारत एक बड़े अवसर का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रहा है। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र से घरेलू बाजारों तक सीमित न रहने और वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों से संबंधित एफटीए प्रावधानों की बेहतर जानकारी हासिल करनी चाहिए और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए गुणवत्ता, मानकों और प्रमाणन में निवेश करना चाहिए।

आरबीआई गवर्नर के अनुसार, भारत का तेजी से विस्तारित होता एफटीए नेटवर्क एमएसएमई के लिए नए बाजारों तक पहुंच, कम लागत वाले गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (ग्लोबल वैल्यू चेन) में शामिल होने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि श्रम-प्रधान एमएसएमई उद्योग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभों को व्यापक स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

संजय मल्होत्रा ने एमएसएमई क्षेत्र को उपलब्ध कराए जा रहे ऋण में सुधार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2026 को समाप्त 12 महीनों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 27 प्रतिशत बढ़ा, जो बैंकिंग प्रणाली के कुल ऋण वृद्धि दर 19.4 प्रतिशत से काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया कुल बकाया ऋण सितंबर 2021 के 17.97 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर 2026 में 42.89 लाख करोड़ रुपए हो गया।

हफ्ते के आखिरी सत्र में फिसला बाजार, सेंसेक्स 989 अंक लुढ़का

मुंबई,एजेंसी। पश्चिम एशिया में बढ़ते हमलों के चलते कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में उछाल के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। इस दौरान प्रमुख बेंचमार्कों सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 989.33 अंक यानी 1.17 प्रतिशत गिरकर 83,339.26 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 50 277.30 अंक यानी 1.07 प्रतिशत गिरकर 25,607.20 पर बंद हुआ।



दिन के कारोबार के दौरान, सेंसेक्स ने 83,208.33 का लो बनाया, जबकि निफ्टी एक समय 25,565.90 के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था। निफ्टी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस और टीसीएस शामिल रहे, जिनमें करीब 5-2.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में बीईएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी और इंडिगो शामिल रहे।

इस दौरान, व्यापक बाजारों ने प्रमुख बेंचमार्कों से बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि निफ्टी मिडकैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में क्रमशः 0.10 प्रतिशत और 0.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेक्टरवार देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.88 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 1.43 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो में 1.48 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी केमिकल में 1.4 प्रतिशत, निफ्टी मेटल में 1.4 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया में 0.53 प्रतिशत और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

एक बाजार विशेषज्ञ ने कहा, रतकनीकी रूप से, 26,000 के स्तर के पास बार-बार गिरावट (रिजेक्शन) देखने के बाद निफ्टी गुरुवार के 'डोजि' लो के नीचे आ गया है। तत्काल सपोर्ट 25,400 पर है, जबकि 25,750 का स्तर रेजिस्टेंस बन गया है। बैंक निफ्टी ने अपने छोटे टाइमफ्रेम वाले 'डबल टॉप' पैटर्न की नेकलाइन को तोड़ दिया है और 63,040.90 पर बंद हुआ है।

अगला सपोर्ट 62,600 पर है, जबकि 63,400 तत्काल रेजिस्टेंस का काम करेगा।विशेषज्ञ ने आगे कहा कि अगर बाजार इन रेजिस्टेंस स्तरों के ऊपर वापस आता है और वहां टिकता है, तो शॉर्ट-टर्म में बिकवाली का दबाव कम हो सकता है। वहीं, अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो बाजार में और गिरावट (करेक्शन) का जोखिम बना रहेगा। निफ्टी का 'डोजि' लो के नीचे जाना और आईटी तथा फाइनेंशियल शेयरों में कमजोरी यह संकेत देती है।

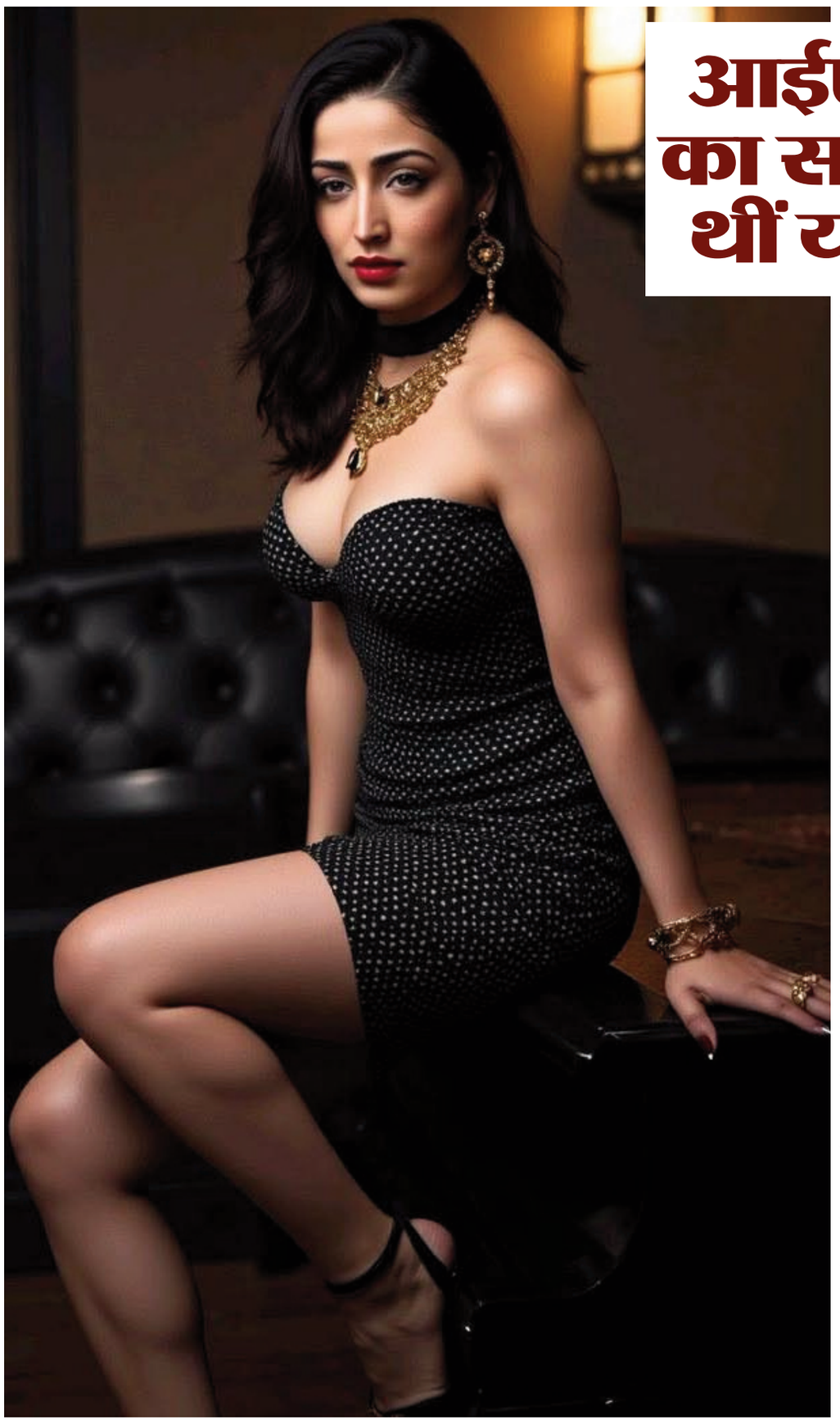

आईएएस बनने का सपना देखती थीं यामी गौतम

मुंबई। मनोरंजन जगत में ऐसे कई सारे सितारें हैं, जिन्होंने करियर कुछ और ही चुना था लेकिन मंजिल कहीं और ही ले गई। ऐसी ही कहानी है अभिनेत्री यामी गौतम की। यामी गौतम आज भले ही बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस बनने से पहले वो आईएएस बनने का सपना देखती थीं? इसके लिए वे सिविल सर्विस की तैयार भी कर रही थीं।

आइए जानते हैं यामी गौतम के आईएएस के सपने से लेकर बॉलीवुड स्टार बनने तक की पूरी कहानी।28 नवंबर को 1988 को बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में जन्मी यामी गौतम की पालन-पोषण चंडीगढ़ में हुआ था। यामी के पिता मुकेश गौतम पंजाबी फिल्म निर्देशक हैं और मां अंजलि गौतम गृहिणी हैं। यामी का बचपन काफी सादा और अनुशासित रहा, जो फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर था।

बताया जाता है कि उनके दादाजी ने चंडीगढ़ में बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया था, जिससे परिवार का जुड़ाव वहीं रहा। स्कूल के दिनों में यामी काफी शर्मीली और अंतर्मुखी स्वभाव की थीं। उन्हें स्टेज पर जाने या परफॉर्म करने से डर लगता था, इसलिए वह स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूर रहती थीं, लेकिन पढ़ाई में अच्छी होने के कारण उनका शुरुआती सपना एक आईएएस अधिकारी बनने का था।

चंडीगढ़ में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद यामी ने लॉ ऑनर्स में दाखिला लिया क्योंकि बचपन और युवावस्था में उनका लक्ष्य लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना था लेकिन उनकी किस्तमत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल, यामी के घर उनके पिता के एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ आए थे, जो टीवी सीरियल से जुड़ी थीं। उन्होंने यामी को देखकर अभिनय के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी तस्वीरें मुंबई के प्रोडक्शन हाउस में भेजीं।

पढ़ाई के बीच मिले अवसरों के बाद यामी ने मॉडलिंग और छोटे पर्दे से शुरुआत की। इससे उनका झिझकने का स्वभाव धीरे-धीरे कम हुआ और अभिनय के प्रति उनकी रुचि बढ़ी। मुंबई आने के बाद विज्ञापन और टीवी शोज किए। अभिनेत्री ने 'चांद के पार चलो' (2008–2009), 'राजकुमार आर्यन' (2008) और 'ये प्यार ना होगा कम' (2009–2010) जैसे टीवी शो में काम किया था, जिसके बाद वे पूरी तरह से फिल्मों की ओर बढ़ गईं।

टीवी में लोकप्रियता हासिल करने के बाद उन्होंने कन्नड़ फिल्म 'उल्लासा उत्साहा' से बड़े पर्दे पर कदम रखा। इसके बाद 'विक्की डोनर' ने उन्हें हिंदी सिनेमा में बड़ा ब्रेक दिलाया। विक्की डोनर के बाद कुछ समय तक उन्हें मनचाहे और दमदार किरदार मिलने में दिक्कत आई, और एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने अभिनय छोड़ने तक का मन बना लिया था।दरअसल, टोटल सियापा', 'एक्शन जैक्सन', 'सनम रे', 'जुनूनियत', 'सरकार 3' और 'बत्ती गुल मीटर चालू' जैसी फ़िल्मों के बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन ने उनके सफर को और मुश्किल बना दिया था।

श्रद्धा कपूर की 'ईठा' के गाने पर झूमीं अक्षरा सिंह, फैंस से बोलीं- 'अब आपकी बारी'



मुंबई। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह इन दिनों अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईठा' के एक गाने के जरिए लोगों का ध्यान खींचा। फिल्म के गाने 'मिर्च मसाला' पर अक्षरा ने एक खास वीडियो बनाया, जिसमें उनका डांस और चेहरे के हाव-भाव गाने के बोल और धुन के साथ मेल खाते नजर आ रहे हैं।

इस पोस्ट में उन्होंने लोगों से अपने लिए भी वीडियो बनाने की अपील की। अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया। इसमें वह 'मिर्च मसाला' गाने पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। गाने की धुन के साथ उनके डांस के अंदाज और चेहरे के हाव-भाव भी देखने लायक हैं। वीडियो के साथ अक्षरा ने कैप्शन में लिखा, "हमारे गाने पर मेरी पहली रील... अब आपकी बारी। आप सभी अपनी फेवरेट श्रद्धा को तो खूब सारा प्यार दें ही, साथ ही एक रील मेरे लिए भी बना देना ना। मुझे टेग जरूर करना, मुझे आपके वर्जन को देखने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं... 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में, 'ईठा' के साथ।"

फिल्म 'ईठा' की बात करें तो यह एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। फिल्म की कहानी महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित है। विठाबाई ने अपने नृत्य और कला के दम पर महाराष्ट्र की लोककला को एक अलग पहचान दिलाई थी।

फिल्म में श्रद्धा कपूर उनकी भूमिका निभा रही हैं। कहानी में एक ऐसी महिला कलाकार का सफर दिखाया गया है, जो तमाम मुश्किलों, निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव और संघर्षों के बावजूद अपनी कला के दम पर पहचान बनाती है। फिल्म में प्यार, धोखा, दर्द, हिम्मत और अपने सपनों को पूरा करने की जिद जैसे पहलुओं को भी दिखाया गया है।

फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, नाना पाटेकर, सिद्धार्थ जाधव, अनंत जोशी, अक्षरा सिंह और उल्का गुप्ता भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। रणदीप हुड्डा फिल्म में विठाबाई के पति अन्ना सावंत मर्चेंट की भूमिका निभा रहे हैं।

भोपाल के थिएटर से मुंबई तक, अर्शी खान ने ऐसे बदली अपनी किस्मत



मुंबई। मनोरंजन जगत में ऐसे कई सितारे हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई और शुरुआती करियर से बिल्कुल अलग राह चुनकर पहचान बनाई है। इन्हीं में से एक नाम अभिनेत्री अर्शी खान का भी है। फिजियोथेरेपी की डिग्री हासिल करने के बाद जहां उनका करियर मेडिकल क्षेत्र में तय माना जा रहा था, वहीं अभिनय के प्रति उनके गहरे लगाव ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।

28 नवंबर को भोपाल के पठान परिवार से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री अर्शी खान ने स्कूल की शिक्षा भोपाल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में जाने का फैसला किया और भोपाल के मायो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। बताया जाता है कि अभिनय की तरफ रुझान होने के कारण अर्शी खान ने भोपाल से थिएटर करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें मॉडलिंग के प्रस्ताव मिले और वह अभिनय व ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़ीं।

दरअसल, अर्शी खान ने अपने करियर के शुरुआती दौर में भोपाल में थिएटर में काम किया, जहां थिएटर निर्देशक एहसान चिश्ती से उन्होंने काम किया। थिएटर के बाद उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिले और उन्होंने कई ब्रांड्स के लिए काम किया; 2014 में वह 'मिस ग्लोरी अर्थ' जैसी सौंदर्य प्रतियोगिता में भी शामिल हुईं।

वहीं, साल 2014 के आसपास उन्होंने तमिल फिल्म 'मल्ली मिशतु' और फिल्म 'द लास्ट सम्राट' (द लास्ट एम्परर) से फिल्मी सफर की शुरुआत की। बाद में वे त्राहिमाम (2022) और अंदाज़ (2024) जैसी परियोजनाओं से भी जुड़ीं।

विदेश

ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा बुशफायर का खतरा

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से में आने वाली गर्मियों के दौरान बुशफायर का खतरा बढ़ गया है। ये चेतावनी अधिकारियों ने दी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नेशनल काउंसिल फॉर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन बुशफायर आउटलुक में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के आठ राज्यों और क्षेत्रों में से छह में आग का खतरा बढ़ा हुआ है।

न्यूजीलैंड में चुनाव के बाद फंसा पेंच

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शुक्रवार को कहा कि अंतिम चुनाव परिणामों के बाद ऑपर्च्युनिटी पार्टी के साथ औपचारिक बातचीत शुरू होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिर सरकार बनाने की कोशिश में बातचीत में समय लग सकता है। सत्तारूढ़ नेशनल के नेतृत्व वाले गठबंधन (जिसमें नेशनल पार्टी, एसीटी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड फर्स्ट शामिल हैं)

भारत की मेजबानी में आईओआरए बैठक के सफल आयोजन की मॉरीशस और श्रीलंका ने की सराहना

नई दिल्ली। 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (आईओआरए) की 25वीं 'काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स' (सीओएम) बैठक के सफल आयोजन के लिए मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने भारत की सराहना की। उन्होंने पिछले एक साल के दौरान इस क्षेत्रीय समूह की अध्यक्षता करने के लिए भी भारत की सराहना की।



सीओएम बैठक में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान रामफुल ने आईओआरए सचिवालय के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि आईओआरए के नए उपाध्यक्ष के रूप में मॉरीशस भारत और अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा, ₹मैं भारत सरकार को इस परिषद बैठक के सफल आयोजन और हमारे यहां पहुंचने के बाद से मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए बधाई देता हूं।

मैं पिछले एक वर्ष में आईओआरए की अध्यक्षता के दौरान भारत के शानदार नेतृत्व की भी सराहना करता हूं। साथ ही, इस बैठक की तैयारी और संगठन के सहयोग एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगातार समर्थन देने के लिए आईओआरए सचिवालय की भी प्रशंसा करता हूं।' रामफुल ने आगे कहा कि यह पहली बार है जब मॉरीशस आईओआरए की बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में हिस्सा ले रहा है। उन्होंने कहा कि इस नई भूमिका में उनका देश अध्यक्ष और सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर संगठन के कामकाज को आगे बढ़ाने, उसकी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और बदलते क्षेत्रीय तथा वैश्विक माहौल में आईओआरए की भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए काम करेगा।

उन्होंने कहा, 'हम इस परिषद बैठक के दौरान सकारात्मक चर्चा और उपयोगी विचार-विमर्श की उम्मीद करते हैं, ताकि ऐसे सार्थक नतीजे निकलें जो संगठन के भविष्य के काम को दिशा दे सकें।'रामफुल ने कहा कि आईओआरए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सदस्य देशों की साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन सकता है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, निवेश और संपर्क का एक अहम मार्ग है। ऐसे में आईओआरए समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश को आसान बनाने, मत्स्य प्रबंधन, पर्यटन, ब्लू इकोनॉमी, आपदा जोखिम प्रबंधन, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक सहयोग और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत कर सकता है।

रामफुल ने कहा, 'अगर सदस्य देश अपनी सामूहिक ताकत, संसाधनों और विशेषज्ञता का सही उपयोग करें तो आईओआरए नए आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बना सकता है और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।' वहीं, श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने 2023 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की कोलंबो यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय जयशंकर ने हिंद महासागर को एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी क्षेत्र बताया था। हेराथ ने कहा कि भारत की मौजूदा अध्यक्षता के दौरान यह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और भारत द्वारा चुना गया विषय क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों के अनुरूप है।उन्होंने कहा, ₹जब आप 2023 में कोलंबो आए थे।

मैक्सिको की राष्ट्रपति ने क्यूबा के साथ एकजुटता दोहराई

मेक्सिको सिटी। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने क्यूबा के साथ अपने देश की एकजुटता को फिर से दोहराया है। उन्होंने कैरेबियाई द्वीप पर लगाए गए किसी भी व्यापार या ऊर्जा नाकेबंदी का विरोध किया और क्यूबा के लोगों के अपने भाग्य को खुद तय करने के अधिकार का बचाव किया। गुरुवार को अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, राष्ट्रपति ने कहा कि मैक्सिको की विदेश नीति लोगों के आत्मनिर्णय के सम्मान में निहित है, और कहा कि किसी भी देश को क्यूबा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।द्वीप राष्ट्र के प्रति अपनी सरकार के रुख पर एक पत्रकार के सवाल के जवाब में शीनबाम ने कहा, 'क्यूबा के भाग्य का फैसला केवल क्यूबा के लोग ही कर सकते हैं, कोई और नहीं।'



दक्षिण एशिया में बाल विवाह की सबसे अधिक दर बांग्लादेश में

ढाका। बांग्लादेश में दक्षिण एशिया के देशों में बाल विवाह की सबसे अधिक दर दर्ज की गई है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (बीबीएस) और यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार, देश में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 47.2 फीसदी महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी।

बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में हर साल करीब 1.2 करोड़ लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। वहीं, दुनियाभर में करीब 65 करोड़ महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं, जिनकी शादी बचपन में हुई थी।यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह के ज्यादातर मामले गरीब परिवारों, कम शिक्षित लड़कियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों से जुड़े हैं। बांग्लादेश में बाल विवाह की दर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है।

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले में दो घरों को बनाया निशाना

क्वेटा। पाकिस्तान की सेना लगातार बलूचिस्तान के नागरिकों को निशाना बना रही है। इसी कड़ी में वाशुक जिले में पाकिस्तानी सेना ने दो घरों पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें एक युवक घायल हो गया।



स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने वाशुक के राघई इलाके में स्थित मुल्ला धुनी गांव में एक सैन्य अभियान के दौरान ड्रोन हमले में दो घरों को निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह ताजा घटना ऐसे समय में हुई, जब बलूचिस्तान में नागरिकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं।

'द बलूचिस्तान पोस्ट' ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी सेना ने केच जिले के बुलेदा में कुचक और उसके आसपास के इलाकों में जमीनी अभियान भी चलाया। एक अन्य घटनाक्रम में, पासनी के कुलांच इलाके में कुंदरी सर दश्त में भी एक अभियान की खबर है। रिपोर्टों के अनुसार, इस दौरान सेना के जवानों के साथ एक सशस्त्र समूह के सदस्य भी थे, जिन्हें स्थानीय लोग 'डेथ स्क्वाड' कहते हैं।

इससे पहले, बलूचिस्तान के सुराब जिले में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में दो महिलाएं घायल हो गई थीं। इस हमले को पूरे प्रांत में चल रही 'सामूहिक सजा' का हिस्सा बताते हुए 'बलूच यकजेहती कमेटी' (बीवाईसी) ने कहा कि बुधवार सुबह पाकिस्तानी सेना ने सुराब के हाजिका इलाके में गोले दागे, जिसमें गुल बीबी नाम की एक बुजुर्ग महिला और आठ साल की एक बच्ची घायल हो गईं। बीवाईसी ने कहा, 'हाजिका के लोगों के लिए ऐसे हमले कोई नई बात नहीं हैं। उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लगातार छापेमारी, धमकियों और सैन्य अभियानों का सामना करना पड़ता है, जबकि राज्य की अपनी सुरक्षा विफलताओं का खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है। पूरे सुराब में डर का माहौल है। मंडोखेल, अनारी और सुरक में रहने वाले लोग पाकिस्तानी सेना की धमकियों और सैन्य अभियानों का सामना कर रहे हैं, जिससे उनका रोजमर्रा का जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है।'संगठन ने आगे कहा, ₹सोलर पैनल तोड़ दिए जाते हैं, कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाया जाता है और परिवारों की आजीविका के साधन छिन जाते हैं। महिलाओं व बच्चों को परेशान और डराया-धमकाया जाता है।



